20 फरवरी, 2026 ☆ वर्ष 35, पृष्ठ संख्या 76, अंक 02

राजस्थान सुजस

राजस्थान बजट

बजट समृद्ध राजस्थान का 2026-27

बजट

समृद्ध राजस्थान का
हर वर्ग के उत्थान का

शब्द भावना

"बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विज़न को आगे बढ़ाएगा।"

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

- राज्य सरकार का एकमात्र ध्येय जनकल्याण है।
- युवाओं के हर सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
- राज्य सरकार विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण राहत दी जा सके।
- हमारी नीतियों और नीयत के केन्द्र में लोककल्याण ही है।
- राजस्थान का बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है।
- राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है।
- राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले दो वर्षों में अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।
- राजस्थान के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते से नई ऊर्जा मिलेगी।
- राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है तथा हम इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनकर उभर रहा है।
- हमारी सरकार ने अनेक नीतियां लागू कीं हैं, जिससे निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार एवं रोजगार सृजन के भी कई नए मार्ग खुले हैं।
- हमारी सरकार के लिए श्रमिकों की सुरक्षा एवं सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में युवाओं के लिए खेल, रोजगार, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे हमारा युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बन रहा है।
- राज्य सरकार विकास और विरासत दोनों को संजोने का कार्य कर रही है।
- हमारी सरकार की नीतियों और त्वरित निर्णयों के कारण राजस्थान देशभर में निवेश का प्रमुख केन्द्र बन गया है।
- हम आगामी तीन वर्षों में विकास की गति को और रफ्तार देकर राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाएंगे।
- राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
- प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- हमारी सरकार खेजड़ी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
- कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया है।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राज्य बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

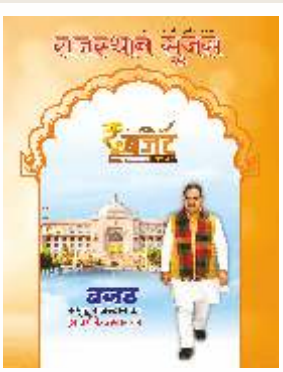

प्रधान संपादक
राकेश शर्मा

वरिष्ठ संपादक
डॉ. गोरधन लाल शर्मा

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
मोहित जैन

संकलन एवं वितरण
ऋतु शर्मा
रणवीर सिंह कुशवाह

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड
लागत मूल्य 47.30 रुपये

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

वर्ष : 35, अंक 02

फरवरी, 2026

इस अंक में

शब्द भावना	02
संपादकीय	04
केन्द्रीय बजट 2026-27	27
समृद्धि का सुनहरा प्रभात	29
जयपुर एयर शो	35
रेडियो - समुदाय, संस्कृति, संचार का सेतु	42
युवा बनें रोजगारदाता...	44
इंडिया स्टोनमार्ट प्रदर्शनी-2026	46
आयुर्वेद की वैश्विक पहचान	50
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024	52
सामयिकी	54
प्रश्नोत्तरी	58
धरोहर	75

राजस्थान बजट 2026-27 **05**

समावेशी विकास की सुदृढ़ नींव **32**

रेत, राग और रोमांच **36**

Pariksha Pe Charcha 2026

परीक्षा पे चर्चा में सफलता के मिले मूलमंत्र **38**

अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन **40**

डिजिटल इंडिया का 'भारत विस्तार' **48**

सरकार @2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष **59**

संपादकीय

समृद्धि और सुशासन के संग
विकसित राजस्थान के विकास स्तम्भ

फाल्गुन का महीना हवाओं में नवचेतना और उल्लास लेकर आता है। सरसों के खेतों की पीत आभा, लोकगीतों की मधुर धुन और रंगोत्सव की आहट वातावरण को जीवंत बना देती है। यह समय केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि नवसृजन का संदेश वाहक भी है। इसी भावना के साथ जब सरकारें अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करती है, तो वह केवल आय-व्यय का विवरण मात्र नहीं होता, बल्कि भविष्य का वह मानचित्र होता है, जिसमें समृद्धि, स्थिरता और अवसरों के विस्तार की दिशा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित रहती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 'विकसित भारत @2047' का संकल्प त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 1 फरवरी को वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह बजट युवा, किसान, श्रमिक, महिला और उद्यमी सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें अवसंरचना, नवाचार, हरित ऊर्जा और कर सुधार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित रूप से शामिल किया गया।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी जी ने 11 फरवरी को राजस्थान सरकार का वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। यह बजट "समृद्ध राजस्थान" की आधारशिला को और मजबूत करता है। साथ ही सेवा, सुशासन और संरचनात्मक सुधार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है। विकसित राजस्थान@ 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस बजट में राज्य सरकार ने आर्थिक समृद्धि, सतत और समावेशी विकास, सेवा, समर्पण और सुशासन को प्राथमिकता दी है। बजट में अर्थव्यवस्था के 10 विकास स्तंभों के माध्यम से विकास का व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रस्तुति से ठीक पूर्व राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों ने सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया। इन शिविरों में बजट के अंतर्गत लिए जाने वाले संकल्पों की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई।

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर से किसानों के लिए समर्पित अभिनव पहल 'भारत विस्तार' का शुभारंभ किया। यह पहल कृषि में डिजिटल और एआई आधारित परिवर्तन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से किसानों को उनके काम की जानकारी स्थानीय भाषा में त्वरित और सटीक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

मुझे विश्वास है कि समृद्ध राजस्थान की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सामूहिक प्रयास, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी क्रियान्वयन इसे नई ऊंचाइयों तक पहुचाएंगे। फाल्गुन की उमंग और नवसृजन की भावना के साथ, राज्य के बजट की प्रमुख पहलों और विकास के रोड मैप को समाहित करते हुए फरवरी माह का यह अंक आप सभी सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

वन्दे मातरम्।

(राकेश शर्मा)
प्रधान सम्पादक

राजस्थान बजट

बजट समृद्ध राजस्थान का 2026-27

11 फरवरी, 2026

‘संकल्प से सिद्धि’, ‘नीयत से नीति’ तथा ‘आकांक्षा से उपलब्धि’ की ओर अग्रसर करने वाला बजट

बजट पूर्व संवाद

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक जनोन्मुखी और सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से जनवरी-फरवरी माह में व्यापक स्तर पर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किए। इन संवादों में युवा एवं खेल क्षेत्र के प्रतिनिधि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े उद्यमी, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, कर सलाहकार, युवा प्रोफेशनल्स, महिला प्रतिनिधि, कर्मचारी संगठनों के सदस्य, छात्राएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, किसान, पशुपालक एवं डेयरी संघों के पदाधिकारी, एनजीओ, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सभी वर्गों से सीधे संवाद कर बजट से संबंधित उनकी अपेक्षाओं, सुझावों और आवश्यकताओं को विस्तार से जाना। प्राप्त सुझावों को संकलित कर वर्ष 2026-27 के बजट में समाविष्ट किया गया, ताकि राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास को नई गति मिल सके और प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं को सार्थक रूप से पूरा किया जा सके।

वर्ष 2026-27 के बजट को पूरा पढ़ने के लिए स्कैन करें।

3 संकल्पों की नींव पर विकास के 10 स्तंभ

"कोष मूलो दण्डः" (अर्थशास्त्र) अर्थात राजकोष ही प्रशासन का मूल आधार है।

शासन की प्रभावशीलता और विकास की निरंतरता वित्तीय सामर्थ्य से ही संभव है। महान दार्शनिक आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राज्य की समस्त दण्डनीति, प्रशासनिक संरचना और नीतिगत क्रियान्वयन का आधार सुदृढ़ कोष व्यवस्था ही है। वित्त को सदैव राज्य-संरचना का केंद्रीय तत्व माना गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही विचार अधिक संस्थागत रूप ग्रहण कर चुका है।

राजस्थान बजट 2026-27 के तीन संकल्प

प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत एवं समावेशी विकास

सेवा, समर्पण और सुशासन को प्राथमिकता

सबका साथ-सबका विकास और सबकी सार्थक भागीदारी

भारत के संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण (सामान्य रूप से जिसे बजट कहा जाता है) का प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्ज किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 (केंद्र सरकार) और अनुच्छेद 202 (राज्य सरकार) के तहत संबंधित विधायिका के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। । इस वार्षिक वित्तीय विवरण में आगामी वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों तथा प्रस्तावित व्ययों का विधिवत उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार बजट केवल लेखा दस्तावेज नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व, नीति-निर्देशन का उपकरण और शासन की उत्तरदायित्व प्रणाली का औपचारिक प्रतिरूप है।

बजट का नीतिगत परिप्रेक्ष्य

लोक वित्त के सिद्धांतों के अनुसार बजट को एक निश्चित अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विधिसम्मत विवरण माना जाता है, किंतु समकालीन प्रशासनिक विमर्श में इसे राज्य की विकास-दृष्टि, संसाधन-संचालन क्षमता और सामाजिक प्राथमिकताओं का दर्पण भी समझा जाता है। बजट के माध्यम से सरकार अपनी आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति को मूर्त रूप प्रदान करती है।

सुदृढ़ वित्त, सशक्त विकास

किसी भी राज्य की विकास यात्रा उसकी नीतिगत स्पष्टता और वित्तीय अनुशासन पर आधारित होती है। बजट इसी संतुलन का आधिकारिक दस्तावेज है। यह केवल आय और व्यय का अनुमान नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और दीर्घकालिक विकास-दृष्टि का औपचारिक प्रस्तुतीकरण है। बजट यह निर्धारित करता है कि राज्य वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेगा।

राज्य बजट 2026

राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए 'विकसित राजस्थान @2047' के विज़न को साकार करने की दिशा में ठोस पहल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य का वर्ष 2026–27 का विकासोन्मुखी बजट, सेवा, समर्पण और सुशासन की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत यह बजट आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही राज्य के दीर्घकालिक और समग्र विकास के लिए 10 प्रमुख संकल्प निर्धारित किए, जिन्हें विज़न डॉक्यूमेंट 'विकसित राजस्थान @ 2047' के अंतर्गत विकास स्तम्भों के रूप में स्थापित किया गया। इस विज़न का उद्देश्य वर्ष 2047 तक राजस्थान को आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। राजस्थान बजट 2026-27 इन्हीं निर्धारित विकास स्तम्भों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं, संसाधनों के अनुकूलतम प्रबंधन, सामाजिक कल्याण योजनाओं, अवसंरचना विकास, रोजगार सृजन तथा निवेश प्रोत्साहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है। इस प्रकार, राजस्थान का बजट केवल वार्षिक आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि 'संकल्प से सिद्धि' की दिशा में राज्य की नीतिगत प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रस्तुत हैं बजट 2026–27 के प्रमुख बिंदु...

राजकोषीय संकेतक

- बजट आकार- 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए
- वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान
  - 3 लाख 25 हजार 740 करोड़ 14 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां
  - 3 लाख 50 हजार 54 करोड़ 7 लाख रुपए का राजस्व व्यय
  - राजस्व घाटा 24 हजार 313 करोड़ 93 लाख रुपए
- वर्ष 2026-27 का राजकोषीय घाटा 79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपए, जो GSDP का 3.69 प्रतिशत है
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2026-27 में बढ़कर 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपए

पहला स्तम्भ

अवसंरचना का विस्तार

सड़क | पेयजल | ऊर्जा

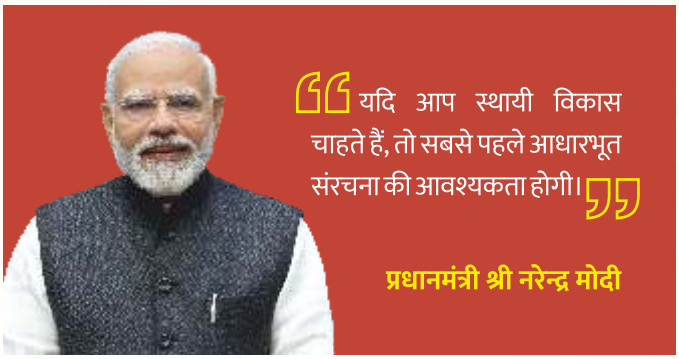

वर्तमान राज्य सरकार शुरुआत से ही प्रदेश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 30 हजार 427 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है, जो कि अब तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है।

सड़क

लक्ष्य

विकसित राजस्थान @2047 के विज़न को साकार करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए रोड नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना, बाइपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट्स का सुधार, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं।

प्रयास

राज्य सरकार के इस कार्यकाल में सड़क विकास पर लगभग 27 हजार 860 करोड़ रुपए का व्यय कर 16 हजार 430 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों को शामिल करते हुए लगभग 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का कार्य किया गया है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए लगभग एक हजार 800 करोड़ रुपए की लागत से State Highways, ROB/ RUB/ Flyover/ Elevated Roads, Bridges आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन।
- नॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए एक हजार 400 करोड़ रुपए तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ रुपए की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित।
- 400 करोड़ रुपए के व्यय के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं Logistic Parks के पहुंच मार्गों का विकास किया जाएगा।
- आगामी वर्ष भी मानसून उपरान्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए।
- ROBs/RUBs पर 920 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय।
- आगामी दो वर्षों में एक हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमार्गों में एवं दो हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा।
- लगभग 500 किलोमीटर लम्बाई के State Highways मय पुलिया व बाइपास 2 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ Intelligent Traffic Management System (ITMS) के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग दो हजार कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे।
- प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन सम्बन्धी कार्य 690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित।

पेयजल

लक्ष्य

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से जहां सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहां सतही जल की उपलब्धता भी काफी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में Robust Governance, Sustainable Conservation एवं Equitable Utilisation के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा है।

> जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। संशोधित समय सीमा के भीतर जल जीवन मिशन के काम पूरे किए जाएंगे और प्रदेश की जनता को गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।
>
> **मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

प्रयास

प्रदेश में 'Universal Access to Safe Water for All' के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को गति देते हुए इसके अंतर्गत 'हर घर नल से जल' सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं तथा 24 हजार करोड़ रुपए की लागत की 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही, परवन अकावद परियोजना के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड़ के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए तथा नवनेरा परियोजना के तहत कोटा एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक हजार 100 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से 5 हजार 830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य कराए जाने की घोषणा की गई थी।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाते हुए 5 हजार करोड़ रुपए का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित।
- अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन।
- एक हजार 92 गांवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तक नवीन Transmission Line (TM-II) सम्बन्धी कार्य।
- आगामी वर्ष 600 Tube wells व एक हजार 200 Handpumps लगाए जाने प्रस्तावित।
- सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में Centre of Excellence की स्थापना की जाएगी।

- Bureau of Water Use Efficiency की स्थापना कर जयपुर में HCM RIPA, सचिवालय एवं जल भवन में pilot basis पर Water Distribution Efficiency के संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।
- पेयजल सुविधा तथा Non-Domestic व Industrial Units के लिए पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत Rajasthan State Water Policy लाई जाएगी।
- राज्य से निकलने वाले Delhi-Mumbai Industrial Corridor के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए एक हजार बारह करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम जलाशय एवं फीडर निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 200 करोड़ रुपए की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेशवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन को बदलने के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 210 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे।

ऊर्जा

लक्ष्य

प्रदेश को विकसित बनाए जाने की दिशा में उत्पादन क्षमता विस्तार एवं Renewable Energy के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर 'हर घर बिजली' व 'हर उद्योग को शक्ति' उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है।

प्रयास

राजस्थान को ऊर्जा प्रदेश बनाए जाने की दिशा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में

- केन्द्रीय उपक्रमों के साथ joint venture के माध्यम से लगभग दो

> प्रदेश का बिजली तंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। कुसुम कम्पोनेंट-सी फीडर लेवल सोलराइजेशन में 2 हजार 329 मेगावाट क्षमता के 898 प्लांट स्थापित किए गए हैं। साथ ही, कम्पोनेंट-ए में हमने 426 मेगावाट के 317 प्लांट स्थापित किए हैं।
>
> **मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

लाख करोड़ रुपए के निवेश की परम्परागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए MoUs किए गए हैं।

- सौर ऊर्जा क्षमता में 19 हजार 209 मेगावाट की वृद्धि हुई है।
- पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत 518 मेगावाट क्षमता के एक लाख 30 हजार से अधिक Rooftop Solar Plants स्थापित किए गए हैं।
- सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 केवी के 2 GSS, 220 केवी के 5 GSS, 132 केवी के 45 GSS तथा 33 केवी के 379 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 केवी के 6 एव 132 केवी के 13 तथा 33 केवी के 110 GSS का निर्माण किया जाएगा।
- बीकानेर में मेहरासर-दीनसर-बराला व सवाईसर-करणीसर भाटियान-बिकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा-सेहुआ क्षेत्र में Joint Venture के माध्यम से लगभग 4 हजार 830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का विकास किया जाएगा।

दूसरा स्तम्भ

नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि

लक्ष्य

आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ-साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायतीराज संस्थाओं का विशेष योगदान है। विज़न@2047 की संकल्पना को साकार किए जाने की दिशा में प्रदेशवासियों को किफायती आवास, मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाए गए Comprehensive Mobility Plan को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर ITMS, Urban Mobility App, सड़क व चौराहा सुधार, Flyover, Underpass, Traffic Solutions, Signal Free Traffic, पार्किंग सम्बन्धी कार्य करवाए जाने की घोषणा। इसके तहत जयपुर हेतु एक हजार करोड़ रुपए को शामिल करते हुए कुल 2 हजार 325 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, पुनरूद्धार एवं उन्नयन सम्बन्धी विविध कार्य लगभग 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे।
- वर्ष 2028-29 तक 'सभी के लिए आवास' हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किए जाने हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के लिए 35 हजार व्यक्तियों को Mason सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 7 लाख Street Lights लगाई जाएंगी।
- प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के Drainage System के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1,020 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने की घोषणा। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए Master Drainage Plan बनाए जाएंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग एवं SDRF के सुदृढ़ीकरण के लिए

"राजस्थान Rising तो है ही, Reliable भी है। राजस्थान Receptive भी है और समय के साथ खुद को Refine करना भी जानता है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बाढ़, भूकम्प, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज व बचाव उपकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए 60 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा तथा अग्निशमन सेवाओं के विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 93 Fire Bikes उपलब्ध कराए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

- आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के Downstream Areas में Early Warning Siren Systems 10 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाएंगे।
- जड़ावता-सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पंचगौरव योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष, जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की Branding तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
- प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के Infrastructure Projects को Innovative Financing सुलभ करवाने के लिए RAJ-SETU (Rajasthan Structured Enabler for Transformative Urban and Infrastructure Financing) Fund की स्थापना की जाएगी।

तीसरा स्तम्भ

औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन

लक्ष्य

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तीव्र औद्योगिक विकास आवश्यक है।

प्रयास

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरा है। राज्य सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित Rising Rajasthan-2024 से जहां एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और Sector Specific Parks की स्थापना ने Manufacturing Eco-system को मजबूत किया है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है।

इसी कड़ी में, राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास तथा Hassle Free निवेश को दृष्टिगत रखते हुए Direct Allotment Policy लागू कर एक हजार 200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसम्बर, 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरन्तर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे।
- लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर Plug and Play Facility for Small and Micro Enterprises स्थापित किए जाने की घोषणा।
- Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) परियोजना के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3 हजार 600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी दो वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश में Logistic Eco-system को विकसित करने के लिए भिवाड़ी के सलारपुर एवं डीडवाना-कुचामन के परबतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नये Logistic Hubs विकसित किए जाने हेतु

निजी क्षेत्र के सहयोग से Inland Container Depot (ICD), Multi-Modal Logistic Hub आदि की स्थापना की जाएगी।

- देश-विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए राज्य सरकार द्वारा Domestic and Overseas Rajasthani Affairs (DORA) विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में Rajasthan Foundation के 26 Chapters कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, New Zealand, Canada आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नये Chapters शुरू किए जाएंगे।
- माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5 हजार Electric Wheels (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- Rajasthan ODOP Policy, 2024 के अन्तर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को margin money उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित।
- कोटा-बूंदी में निर्माणाधीन नवीन Green Field Airport के नजदीक रीको द्वारा वृहद् औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें Logistic, Textile आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
- जोजरी व बांडी नदी में गिरने वाले Treated Water को पाइप लाइन द्वारा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा तक पहुंचाने के कार्य के लिए DPR बनाई जाएगी।

चौथा स्तम्भ

मानव संसाधन का सशक्तीकरण

युवा विकास एवं कल्याण | **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**

लक्ष्य

विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका एवं योगदान महत्त्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने।

प्रयास

राज्य सरकार ने युवाओं के लिए Vocational Education, Skill Enhancement, Career Counselling के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष focus किया है। साथ ही, प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए employable बनाए जाने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत एक लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा Margin Money अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी, जिस पर एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, इस योजना से 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
- National Testing Agency (NTA) की तर्ज पर प्रदेश में Rajasthan State Testing Agency (RSTA) की स्थापना की जाएगी।
- Startups के विकास के लिए VIBRANT (Value-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing Talent) Programme चलाया जाएगा।
- 150 महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रों की स्थापना कर लगभग 25 हजार छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, career guidance तथा digital mentoring के उद्देश्य से DREAM (Digital Readiness and Empowerment through Assisted Mentoring) Programme चलाया जाएगा, प्रथम चरण में लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
- 'नशा मुक्त राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने के लिए Raj-SAVERA (Statewide Anti-drugs Vigilance Enforcement Rehabilitation and Awareness) कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- हर जिले में Industry Partners को जोड़ते हुए Institute of Skill Development and Vocational Training प्रारम्भ किए जाएंगे।

- उभरते Startups की Mentorship व Scaling के लिए iStart Ambassador Programme प्रारम्भ किया जाएगा।
- Next Generation Technology से युक्त नवीन Techno Hubs की स्थापना, 30 करोड़ रुपए का व्यय।
- कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर Tablet/ Laptop क्रय किए जाने के लिए e-Voucher के माध्यम से 20 हजार रुपए तक की सहायता।
- 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरत मंद छात्राओं को साइकिल हेतु e-Voucher.
- कक्षा 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क Uniform उपलब्ध कराने के लिए DBT की जाएगी, लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय।
- प्रदेश के Toilet सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में Toilets बनाए जाने प्रस्तावित है।
- 2 हजार 500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपए व्यय।
- Raj PAHAL (Portable Access for Holistic and Assisted Learning) कार्यक्रम आरम्भ किए जाने की घोषणा, प्रत्येक जिले में एक School on Wheels स्थापित किया जाएगा।
- प्रदेश के एक हजार विद्यालयों में AI आधारित Personalised Learning Labs की स्थापना की जाएगी।
- 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM-RISE (Rajasthan Innovative School of Excellence) स्कूलों में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा, एक हजार करोड़ रुपए का व्यय।
- प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से नवीन संस्थान व विषय प्रारम्भ करने तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।
- 'खेलो राजस्थान Youth Games' के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन, 50 करोड़ रुपए व्यय।
- IIIT कोटा में AI, Data Analytics तथा अन्य emerging क्षेत्रों में नए courses प्रारम्भ करने एवं IIIT कोटा को IT के बड़े Hub के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से DPR बनाई जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- सड़क दुर्घटना, प्रसूति, Heart Attack जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए RAJ-SURAKSHA (Rajasthan System for Urgent Response, Accident Stabilization and Hospital Access) योजना लागू किए जाने की घोषणा।
- 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य' के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ बदलती जीवनशैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिन्ता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु Raj-MAMTA (Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All) Programme चलाया जाएगा।
- जिला मुख्यालयों पर Mental Health Care Cell की स्थापना।
- जेकेलोन चिकित्सालय-जयपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से 500 bed क्षमता के IPD Tower की स्थापना की जाएगी।
- चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त Drug Distribution Counters की स्थापना की जाएगी।
- जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे।
- अटल आरोग्य फूडकोर्ट की स्थापना की जाएगी, सौ करोड़ रुपए व्यय।
- मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की mortuary (शव गृह) से सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए 'मोक्ष वाहिनी योजना' शुरू की जाएगी।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, upgradation, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
- मेडिकल कॉलेज-कोटा में Robotic Hand for Prostatic Surgery for Urology की सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। साथ ही, इससे सम्बद्ध चिकित्सालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- प्रदेश के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य व नेत्र जांच शिविर आयोजित कर लगभग 75 हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच कर यथा आवश्यकता चश्में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

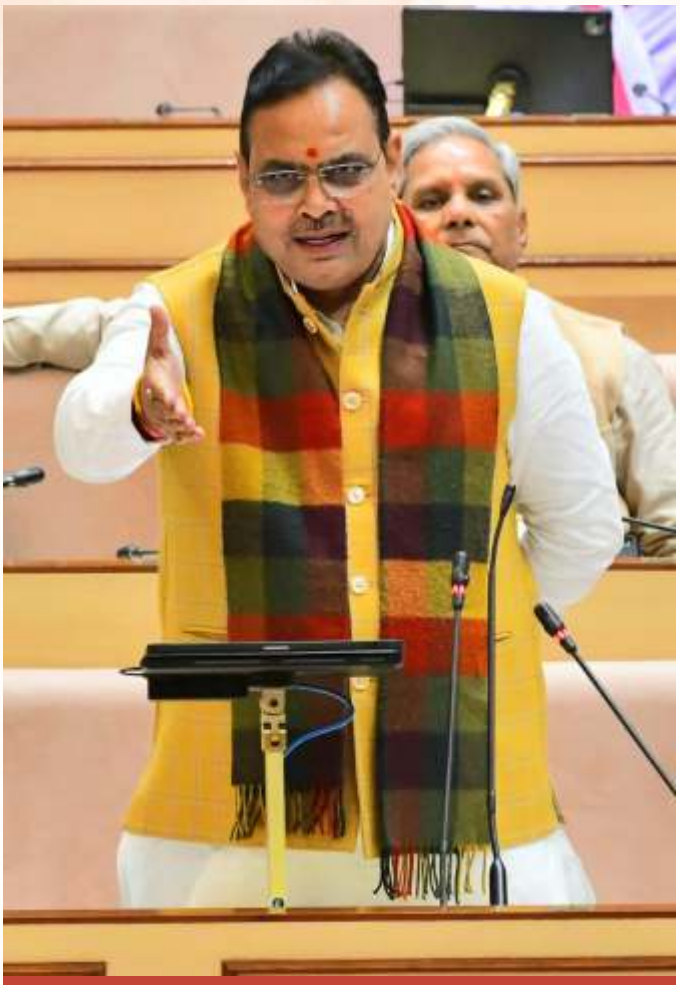

"विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है। पालनहार योजना के तहत 6 लाख 15 हजार से अधिक परिवारों को संबल दिया गया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 16 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। वहीं, 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण एवं डिजिटल तकनीक से जोड़कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया गया है।"

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

पांचवां स्तम्भ

सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विभिन्न वंचित वर्गों के कल्याण के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान तथा समग्र विकास के लिए संवेदनशील है। महिला सशक्तीकरण एवं Financial Inclusion के दृष्टिगत 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर पर Rural Women BPO स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- साथ ही, महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अन्तर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपए किए जाने की घोषणा।
- राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 Cluster Level Federations (CLFs) के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में Digital एवं Financial Literacy के लिए 'Saksham Centres' भी संचालित किए जाएंगे। इस हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
- राजीविका की स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर बीसी (Banking Correspondent) सखी बनाया जाएगा। साथ ही, एक हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाएगा।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहतर Branding, Designing, Packaging कर बिक्री में वृद्धि किए जाने के लिए राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से समन्वय कर आगामी वर्ष Dairy, Textile, Footwear, Millets, मसाले आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के 50 नवीन Enterprises स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
- राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक capital की व्यवस्था करने के साथ क्षमता संवर्द्धन एवं Marketing आवश्यक है। इस हेतु समस्त संभागीय मुख्यालयों पर 'Raj Sakhi Stores' प्रारम्भ किए जाएंगे। क्षमता संवर्द्धन हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से Centre for Entrepreneurship and Capacity Building स्थापित किए जाएंगे।
- प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत महिला/SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा।
- प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में Mid-Day Meal के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिला SHGs के आजीविका संवर्द्धन की दृष्टि से 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किए जाने की घोषणा। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण Early Childhood Care एवं Pre-School Education उपलब्ध कराने के लिए

'Rajasthan State Early Childhood Care, Development and Education Policy' बनाई जाएगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को Early Childhood Care and Education Course करवाया जाएगा।
- 7 हजार 500 आंगनबाड़ियों को 'नन्द घर' के रूप में विकसित किए जाने के लिए 225 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय भवनों में संचालित 17 हजार 95 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत Connections कराए जाएंगे।
- प्रदेश में भरतपुर तथा कोटा में समेकित बाल विकास सेवाएं तथा महिला अधिकारिता कार्यालयों के लिए 'महिला एवं बाल शक्ति संकुल' बनाए जाने प्रस्तावित।
- वर्तमान में Aspirational जिलों-करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित किशोरी बालिका योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 Aspirational Blocks में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित। इससे योजनान्तर्गत 50 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी।
- प्रदेश में जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों की समुचित देखभाल व संरक्षण की दृष्टि से बाल देख-रेख संस्थाओं, Observation Homes, Children Homes आदि की स्थापना एवं विकास के कार्य लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे।
- राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह, जामडोली-जयपुर में बालक व बालिका विंग की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 42 आवासीय विद्यालयों के 15 हजार विद्यार्थियों को बेहतर Learning Outcome तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के उद्देश्य से IIT, दिल्ली के सहयोग से AI आधारित 24×7 Live Academic Mentoring की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों को उच्चतर शिक्षा एवं Employment Oriented प्रशिक्षण के लिए उनकी रुचि अनुसार विकल्प प्रदान करते हुए Industry Linked Employment अवसर उपलब्ध कराने के लिए online platform विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश के जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादों की Processing हेतु बांसवाड़ा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर Minor Forest Produce Processing Centres स्थापित किए जाएंगे।
- श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हेतु श्रम-सेतु Mobile App शुरू किया जाएगा।
- बालिकाओं व महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक Counselling, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों, Cyber Fraud से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI (Safety Training Resource Initiative) योजना प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत लगभग एक लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

छठा स्तम्भ

पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर

राजस्थान देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रणी पसंद है। पर्यटन विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति, 2025 लागू की गई है। इसके साथ ही प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केन्द्र बिन्दु बनाने की दिशा में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025 भी लागू की गई है। 'विकास भी, विरासत भी' की सोच के साथ राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों के लिए Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) का गठन भी किया गया है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक ग्रामीण, वैश्विक व Eco-tourism तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ-साथ हैरिटेज संरक्षण व धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
- प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को धरातल पर लाने की दृष्टि से High Impact Last Mile Infrastructure का निर्माण करते हुए

पर्यटकों के on ground tourist experience को चिरस्थाई व यादगार बनाए जाने की कड़ी में पर्यटन एवं Hospitality की दृष्टि से खुड़ी-जैसलमेर में ultra luxury Special Tourism Zone (STZ) विकसित किया जाएगा। साथ ही, कुलधरा में पर्यटक सुविधा केन्द्र विकसित किया जाएगा।

- पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी एवं मण्डावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को Model Road के रूप में विकसित किए जाने एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
- भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
- प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परम्परा का प्रतीक हैं। इनको भावी पीढ़ियों के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।
- शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।
- पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवनशैली, लोक कला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए 'थार सांस्कृतिक सर्किट' बनाए जाने की घोषणा।
- वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से झुंझुनूं में War Museum की स्थापना की जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू (नेपाल) तथा 50 हजार वरिष्ठजन को AC Train से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाना प्रस्तावित है।
- Rural Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए Home Stay चलाने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा एवं Hospitality Management में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- गैर, पद दंगल, भवाई, घूमर जैसे लोक नृत्य हमारे प्रदेश की अनुपम सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को इन लोक नृत्यों से जोड़ने के लिए संभाग स्तर पर 'लोक नृत्य उत्सव' आयोजित करवाए जाएंगे।
- पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग हेतु पर्यटन सहायता बल (TAF) कैडर का सुदृढ़ीकरण करते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों एवं Guides की भी नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवस्थान विभाग के अधीन रिक्त भूमि पर धर्मशालाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु Build-Operate-Transfer (BOT) आधारित नवीन नीति बनाई जानी भी प्रस्तावित है।
- राज्य में बेहतर Air connectivity उपलब्ध कराने के लिए सीकर-झुंझुनूं तथा भरतपुर-डीग क्षेत्र में नवीन Airports स्थापित किए जाने हेतु Feasibility Study करवाई जाएगी। साथ ही, सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में Flying Training Organisations (FTOs) स्थापित किए जाएंगे।
- हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व, चम्बल घड़ियाल सेन्चुरी में सफारी एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

सातवां स्तम्भ

सुशासन एवं डिजिटल

डिजिटल शासन पारदर्शी प्रशासन | **कानून व्यवस्था** | **कार्मिक कल्याण**

मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

डिजिटल शासन, पारदर्शी प्रशासन

प्रयास

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं जन सहभागिता के आधार पर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। विकसित राजस्थान के लिए AI आधारित जनसेवा सुधार, मजबूत नीतिगत ढांचा निर्माण, जागरूकता व Skill Enhancement पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही, Paperless Governance एवं सशक्त साइबर सुरक्षा के माध्यम से Secured एवं Hassle Free Service Delivery सुनिश्चित की गई है। इससे प्रदेश डिजिटल शासन एवं पारदर्शी प्रशासन की ओर अग्रसर हुआ है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए Next Generation Citizen Service Reforms लाए जाने की घोषणा।
- वर्तमान में प्रदेशवासियों को e-Mitra के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को WhatsApp Platform पर भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है।
- Digital Infrastructure Facilitation Policy लाई जाएगी।
- स्वास्थ्य, उद्योग व पर्यावरण जैसे आमजन से जुड़े क्षेत्रों पर केन्द्रित AI के दो Centre of Excellence स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त AI Infrastructure, प्रशिक्षण, e-Governance, Accounting System सम्बन्धी विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
- मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को 'Mini e-Mitra' के रूप में अधिकृत किया जाएगा।
- Geo Spatial Policy लाई जाएगी।
- Result oriented जनकल्याणकारी योजनाओं की संरचना व evidence based नीति निर्माण के लिए Dedicated Data and Policy Strategy Unit-CM PRAMAN (Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में Drone के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए Drone Policy बनाई जाएगी। साथ ही, बेहतर कार्ययोजना व प्रबंधन के लिए State Drone Cell का गठन कर AI/ML based Data Repository भी बनाई जाएगी।
- Ease of Doing Business की दृष्टि से सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित किए जाने के साथ ही राजकोष के जनहित में सर्वोत्तम उपयोग के लिए आगामी वर्ष Single Holistic Procurement Portal (SHPP) शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से विगत 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में अपराधों में 14.13 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत तथा महिला अपराधों में 10 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

कानून व्यवस्था

- आम नागरिकों को 'Digital Arrest' की घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C) की स्थापना की जाएगी। आमजन को अपने घर से ही उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में Video Conferencing की सुविधा प्रदान की जाएगी।

कार्मिक कल्याण

- राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर के training courses की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से 'Rule based' से 'Role based' कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे।
- राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु 'Salary Account Package' लाया जाएगा। इसके अन्तर्गत salary account के साथ advanced digital बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दर पर ऋण तथा बीमा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से 'मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन' खोले जाएंगे।
- राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर State Panchayat Awards दिए जाने प्रस्तावित हैं।
- लूणकरणसर-बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाएगा।
- गोविन्दगढ़-अलवर में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) तथा झोटवाड़ा-जयपुर में सहायक अभियंता (विद्युत) के कार्यालय खोले जाएंगे।
- साथ ही, सर्किट हाउस अजमेर में Cottage एवं VIP Suite युक्त विंग का निर्माण किया जाएगा।
- आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए चाबा (शेरगढ़) जोधपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा धावा (लूणी)- जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा।
- राज्य में निजी Helicopter एवं विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया हेतु आवश्यक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए Single Window Clearance System लागू किया जाएगा।
- राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्ति से दो वर्ष की अवधि में राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों/संस्थानों में नियुक्ति होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर कार्मिकों से भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी।
- सभी राज्य कर्मचारियों को Extended Insurance Maturity के साथ अधिवार्षिकी retirement तिथि तक Insurance Cover उपलब्ध कराया जाएगा।

आठवां स्तम्भ

कृषि विकास एवं किसान कल्याण

कृषि बजट

लक्ष्य

कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था- "सच्ची प्रगति ग्रामीण एवं कृषि आधार को सुदृढ़ करने में निहित है।" राज्य सरकार वर्ष 2047 तक राजस्थान को Technology Driven अग्रणी कृषि शक्ति बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रयास

कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की Processing एवं Marketing सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है। सीकर, झुंझुनूं, चूरू एवं अन्य जिलों की पिछले 30 वर्षों से लम्बित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने हरियाणा से MoU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- 11 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित।
- आगामी वर्ष 50 हजार सोलरपम्प संयंत्रों पर एक हजार 500 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किस्तों की राशि 1 अप्रेल 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट की घोषणा।
- विभिन्न कृषि यंत्रों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper आदि हेतु 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित, इससे लगभग 50 हजार कृषक लाभान्वित होंगे।
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर 70 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित, 50 करोड़ रुपए का व्यय। इससे 3 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
- 500 Custom Hiring Centres की 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना की जाएगी।
- 5 हजार कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
- कृषकों को data driven consultancy services, precision input management, crop planning support व market intelligence की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Agri Stack PMU का गठन किया जाएगा।
- Knowledge Enhancement Programme के अन्तर्गत आगामी वर्ष 3 हजार 300 किसानों को राज्य से बाहर Exposure Visit करवाई जाएगी।
- Green house–Polyhouse/Shadenet, Low Tunnel, Plastic Mulch उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष में 4 हजार कृषकों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- Vertical Support System आधारित खेती हेतु 5 हजार कृषकों को अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
- कृषकों को अनुदानित 500 Solar Crop Dryers उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण, 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर व्यय की घोषणा।
- दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 590 करोड़ रुपए के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान , लगभग 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।

- राज्य के और विशिष्ट Agro-Processed Products को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मिशन Raj GIFT (Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods)
- प्रदेश में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50-50 गोदामों का निर्माण, लगभग 20 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- 200 नवगठित गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं कार्यालय भवन मय चारदीवारी निर्माण, 30 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के Conclave on Spices का आयोजन।
- अलवर में Centre of Excellence for Onion and Vegetables.
- श्रीगंगानगर में Centre of Excellence for Kinnow.
- बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Mango.
- जोधपुर, कोटा व उदयपुर में Organic Food Market की स्थापना।
- प्रदेश के चयनित जिलों में 2 हजार कृषकों, Processors, व्यापारियों व निर्यातकों को प्रशिक्षण।
- नवीन कृषि उपज अनाज मण्डी-बागीदौरा-बांसवाड़ा, सिकराय-दौसा, राजियासरस्टेशन (सूरतगढ़) -श्रीगंगानगर, सब्जीमण्डी-सवाई माधोपुर, बयाना -भरतपुर।
- नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार।
- समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केन्द्र।
- किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए Shed निर्माण सहित मण्डियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों में अन्य आधारभूत कार्यों के लिए 350 करोड़ रुपए व्यय होगा।

पशुपालन एवं डेयरी

- 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र।
- 25 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत।
- 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत।
- Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund की राशि एक हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपए।
- NCR उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के Outlets, 100 करोड़ रुपए का व्यय।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना, 700 करोड़ रुपए का अनुदान, लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार नवीन दुग्ध संकलन केन्द्रों की स्थापना।

"कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं। किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 10 हजार 508 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। वहीं, 48 हजार 325 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किए गए हैं।"

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

- अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के Milk Processing Plant, 200 करोड़ रुपए का व्यय।
- 500 डेयरी बूथ का आवंटन।
- एक लाख पशुपालकों को value added दुग्ध आधारित उत्पाद- शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किए जाने के लिए प्रशिक्षण करवाया जाएगा।
- तबीजी-अजमेर में Poultry Feed Unit स्थापित की जाएगी।

नवां स्तम्भ

हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता

हरित बजट

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए Modified Budget में सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में जहां पिछले वर्ष राज्य के पहले हरित बजट (Green Budget) हेतु प्रदेश सरकार ने 27 हजार 850 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया था, वहीं आगामी वर्ष के लिए 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 33 हजार 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

- 'हरियाळो-राजस्थान' के अन्तर्गत आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित।
- राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत 'नमो नर्सरी' की स्थापना की जाएंगी।

- प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से 'नमो वन' विकसित किए जाएंगे।
- अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान 'Oxyzones' के रूप में विकसित किए जाने हेतु 32 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
- चित्तौड़गढ़ में कुम्भा बायोलॉजिकल पार्क, 31 करोड़ रुपए का व्यय
- वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष PRITHWI (Project for Resilient and Integrated Terrestial Habitats and Wildlife Valorization Initiative) परियोजना, एक हजार 500 करोड़ रुपए का व्यय।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान(MJSA) 2.0 के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5 हजार गांवों में 2 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत से Water Harvesting Structures के एक लाख 10 हजार कार्य करवाए जाने की घोषणा।
- वनभूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर-वनभूमि से एक हजार हेक्टेयर का Land Bank.
- अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तथा जयपुर में Specialised Centres for Treatment of Wild Animals खोले जाएंगे।
- भरतपुर, सांभर-जयपुर व मीठड़ी-कुचामन में Specialised Centres for Treatment of Avian Diseases.
- बनेड़ा (शाहपुरा)-भीलवाड़ा में Eco-Park, टोडारायसिंह-टोंक में नेचरपार्क।
- वन्य क्षेत्रों में Mobility बढ़ाने तथा वन्यजीव Rescue प्रणाली के संवर्द्धन के लिए Rapid Mobility Teams के गठन के साथ ही 291 Wildlife Ambulances, 25 करोड़ रुपए का व्यय।
- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर में Centre of Excellence for Natural Farming की स्थापना।
- नगर निगम जयपुर एवं जोधपुर में PPP Mode पर Compressed Bio Gas Plants की स्थापना।
- Air Quality Monitoring के लिए जोधपुर में भी Early Warning Systems.
- पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रों में Research and Development हेतु जयपुर में 'State of the Art' प्रयोगशाला।
- 20 करोड़ रुपए की लागत से NCR क्षेत्र में थानागाजी-अलवर; बहरोड़, नीमराणा-कोटपूतली बहरोड़; तिजारा-खैरथल तिजारा तथा बयाना-भरतपुर में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS).
- Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) में Research and Development Cell की स्थापना।
- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में Noise Monitoring Stations.
- समस्त जिलों में शवदाह के लिए Closed Combustion Cremation Furnace की स्थापना।
- किसानों को Carbon Credits दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पहली बार Carbon Credit Pilot Project.
- प्रदूषण को कम करने तथा Industrial Waste Water के समुचित उपचार हेतु Common Effluent Treatment Plants (CETPs), बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर CETP निर्माण हेतु एक हजार करोड़ रुपए का व्यय।
- नगरीय निकायों हेतु Solid Waste Management Policy.

दसवां स्तम्भ

2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था

राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सरकार का ध्येय है कि Strategic Financial Planning, Financial Stability व Citizen Centric सुशासन को सुदृढ़ करें, जिससे राजस्थान विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो।

राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान @ 2047 के सपने को साकार

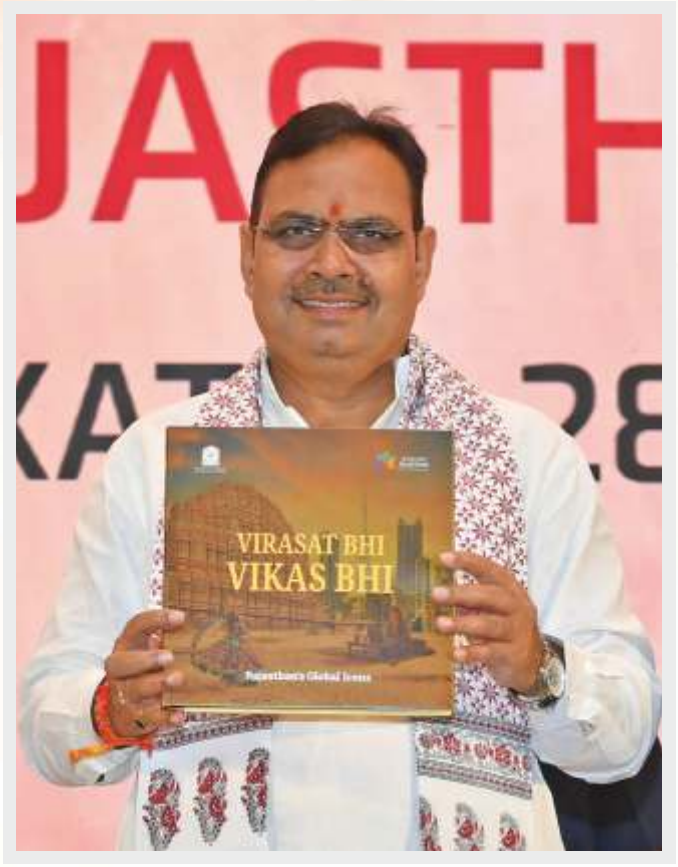

करने के लिए Vision Document के अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास का Road Map प्रस्तुत किया है। अन्नदाता की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है। जहां एक ओर नवीनतम तकनीकों पर आधारित कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों के कल्याण के लिए इस बार के कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में पर्यटन, फिल्म प्रोत्साहन, AI/ML जैसी नीतियों के लागू होने से सर्विस सेक्टर को भी गति मिली है, जिसके फलस्वरूप सर्विस सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 5.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 11.15 प्रतिशत हो गई है।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन (RIPS), निर्यात संवर्द्धन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल एवं वस्त्र, MSME, उद्योग संवर्द्धन जैसी प्रगतिशील नीतियां लागू की गई हैं। इससे प्रदेश का Investment Climate बेहतर हुआ है, निवेशकों का राजस्थान की विकास यात्रा में विश्वास बढ़ा है व प्रदेश में निवेश को नई ऊंचाई मिली है। इन प्रयासों से प्रदेश में निवेश, सुशासन व औद्योगिक विकास के लिए Friendly Eco-system स्थापित हुआ है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, प्रगतिशील सोच के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से सभी Sectors में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, Multiplier Effect उत्पन्न होगा और अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी।

₹ कर प्रस्ताव

“बरषत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोइ।
तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ।”

गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह दोहा आदर्श शासन-व्यवस्था में कर संग्रह और उसके उपयोग का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि जैसे सूर्य (भानु) नदी और तालाब से जल सहज रूप से ग्रहण करता है और बाद में बादलों के माध्यम से वर्षा कर सबको प्रसन्न करता है, कुशल शासक को प्रजा से वैसे ही कर संग्रहित कर उसे उनके विकास और कल्याण में उपयोग करना चाहिए।

प्रयास

आर्थिक विकास को गति देते हुए आमजन, किसानों, श्रमिकों, युवाओं और उद्यमियों पर कर का भार यथासंभव न्यूनतम रखा जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार की कर नीति का मूल आधार है – “कर में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता और प्रशासन में पारदर्शिता।” इसका उद्देश्य है कि कर संग्रह न केवल पारदर्शी और सरल हो, बल्कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाए और विकास को सशक्त बनाए। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार कर प्रणाली को जनहितकारी, विकासोन्मुखी और सुशासन के अनुरूप बनाती है।

महत्त्वपूर्ण घोषणाएं

- GST Tax Payers की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहां ऑनलाइन सुनवाई का Module विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की आगामी तिथि आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही ये सूचनाएं SMS के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेंगी।
- GST करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से Registration संबंधी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन में निस्तारित किया जाएगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- राज्य सरकार पंजीयन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने हेतु e-Registration व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पक्षकारों के e-verification, Slot Booking, Online Registration तथा Digitally Certified Copies प्राप्त करने की सुविधाएं आमजन को घर बैठे ही उपलब्ध होंगी।
- 50 के स्थान पर सभी 106 पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालयों को

मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा।

- MSME उद्यमियों हेतु स्टाम्प ड्यूटी राहत को अब केवल बैंकों और कुछ ऋण दस्तावेजों तक सीमित न रखकर, सभी वित्तीय संस्थानों एवं सभी प्रकार के ऋणों तक विस्तारित करते हुए, स्टाम्प ड्यूटी की दर 0.125 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा।
- आमजन और निवेशकों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रुपए किए जाने की घोषणा।

परिवहन विभाग

- 16.5 मैट्रिक टन से भारी माल वाहक वाहनों पर देय Motor Vehicle Tax के प्रतिवर्ष भुगतान के साथ-साथ वाहन मालिकों को राहत देते हुए एकबारीय भुगतान का भी विकल्प दिया जाना प्रस्तावित।
- वाहन-जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर-परिवहन वाहनों पर देय Green Tax की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा।
- अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाये गए गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर Motor Vehicle Tax में देय अधिकतम 25 प्रतिशत छूट को बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत तक किए जाने की घोषणा।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- खातेदारी भूमि तथा खनन पट्टों एवं क्वारी लाईसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1.00 हैक्टेयर एवं 0.18 हैक्टेयर से कम सरकारी भूमि का खनन/क्वारी प्रयोजनों के लिए आवंटन किए जाने का प्रावधान नहीं होने से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में खनन/क्वारी प्रयोजनों हेतु आवंटन के प्रावधान किए जाने की घोषणा।
- आगामी वित्तीय वर्ष में Major Minerals के 10 Blocks तथा Minor Minerals के 100 Plots की नीलामी Pre Embedded Clearance के साथ किए जाने की घोषणा।
- प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण एवं बजरी पर निर्भरता कम करने हेतु लाई गई M-Sand Policy-2024 के अन्तर्गत राजकीय निर्माण कार्यों में M-Sand के न्यूनतम 25 प्रतिशत उपयोग को Applicable Codes and Standards की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध रूप से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
- खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किए जाने की घोषणा।
- अवैध खनन की रोकथाम तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से खनिज विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित। इसके तहत खनिज अभियन्ताओं एवं भू-वैज्ञानिकों के 15 नये कार्यालय खोले जाने के साथ-साथ 10 AME कार्यालयों को ME कार्यालयों में क्रमोन्नत भी किया जाएगा।
- भारत सरकार की Critical Mineral Strategy (2023-2047) तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप राज्य में Artificial Intelligence & Machine Learning तकनीक का उपयोग कर Critical and Strategic Mineral Exploration को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश में भी पर्यावरण संतुलन के साथ सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिये स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले खानधारकों को सम्मानित भी किया जाएगा।
- राज्य में खनिज अन्वेषण को नई गति देने के लिए Base Metal, Limestone, Manganese & Iron जैसे खनिजों हेतु जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य किया जाएगा तथा Base Metal Limestone, Manganese & Iron जैसे खनिजों हेतु जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य किया जाएगा तथा Geological Survey of India के सहयोग से "स्टेट ऑफ आर्ट-खनिज कोर लाइब्रेरी" की स्थापना की जाएगी।
- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में EV तथा CNG वाहन प्रमुख विकल्प हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नये सीएनजी स्टेशन तथा 250 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर परिधि में, Eco Sensitive Zone Notification के अभाव में बन्द रहे खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंसों की इस अवधि को Deemed Non-Working Period घोषित किया जाना प्रस्तावित।

उद्योग व वाणिज्य

- वर्ष 2047 तक राज्य की GDP को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है।
- इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान GDP के 80 प्रतिशत से अधिक होना लक्षित है। इससे व्यापक रोजगार, सशक्त उद्यमिता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।
- निवेशकों और उद्योगों के लिये राज्य को Destination State के रूप में विकसित करने हेतु Single Window 2.0 Platform लागू किए

जाने की घोषणा। इसके अंतर्गत "एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक" के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी।

- विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जांच व्यवस्था को Risk-Based करते हुए कम जोखिम वाले मामलों में भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों में लक्षित कार्यवाही की जाएगी।
- राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा RIPS Portal का Integration कर RIPS के तहत निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल किए जाने की घोषणा।
- राज्य के परम्परागत एवं श्रम प्रधान टैक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु RIPS-2024 के तहत इस उद्योग को Capital Subsidy, TLI एवं SGST पुनर्भरण के साथ-साथ Payroll Subsidy के रूप में Asset Creation Incentive का एक अतिरिक्त विकल्प दिए जाने की घोषणा।
- RIPS-2024 के अन्तर्गत Interest Subvention का लाभ मैन्यूफैक्चरिंग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी दिए जाने की घोषणा।
- सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC तथा Warehouse & Logistics सेक्टर्स को भी RIPS-2024 के अन्तर्गत Expansion के लाभ अनुमत किए जाने की घोषणा।
- राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का Manufacturing Ecosystem विकसित किए जाने के उद्देश्य से Integrated Solar Cell & Module निर्माण इकाइयों को भी RIPS-2024 के तहत देय लाभों के लिए सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित।
- Export Oriented Industrial Development को बढ़ावा देने हेतु Container Manufacturing को RIPS-2024 के अन्तर्गत Thrust Sector के रूप में सम्मिलित किए जाने की घोषणा।
- देश और राज्य में हरित रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य में 'Energy Transition Skilling Cluster' विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से Renewable Energy, ई-व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा।
- राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी-2024 के तहत Expansion हेतु ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10 प्रतिशत Margin Money Assistance दिया जाना प्रस्तावित।

कृषि बजट

कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 में समेकित निधि, राज्य की स्वायत्तशासी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1 लाख 19 हजार 4 सौ 8 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 69 हजार 4 सौ 22 करोड़ 99 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है, जो राज्य के कुल बजट का 11. 36 प्रतिशत है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट GSDP का 5.55 प्रतिशत है।

ग्रीन बजट

प्रदेश में दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित राजस्थान' बनाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीन बजट में 33 हजार 4 सौ 75 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74 प्रतिशत है तथा कुल बजट का 5.48 प्रतिशत है, जो कि गत वर्ष से 20.18 प्रतिशत अधिक है।

केंद्रीय बजट 2026-27

"यह बजट अपार अवसरों का द्वार है, जो वर्तमान सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करता है। भारत जिस सुधार की रफ्तार पर चल रहा है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। बजट में बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, उच्च तकनीक उपकरण निर्माण को प्रोत्साहन देना और अग्रणी लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तैयार करना जैसे उभरते क्षेत्रों को दिया गया अभूतपूर्व समर्थन दूरदर्शी है और राष्ट्र की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करता है।"

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

केन्द्रीय बजट 2026-27 : मुख्य हाईलाइट्स

- भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्ष के लिए दस हजार करोड़ रुपए।
- तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एन.आई.पी.ई.आर.) के निर्माण तथा सात मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क।
- खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।
- एम.एस.एम.ई. को चैंपियनों के रूप में विकास करने में सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत।
- आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे।
- कार्बन टैक्चर उपयोग और भंडारण (सी.सी.यू.एस.) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा।
- तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुम्बई को 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और पांच सौ महाविद्यालयों में ए.वी.जी.सी. कंटेंट क्रिएटर लैब (सी.सी.एल.) स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी।
- आई.टी. सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को तीन सौ करोड़ रुपए बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपए किया जा रहा है।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को पुनर्जीवित कर उत्कृष्ट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बनाया जाएगा।
- सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स (SHE Marts) समुदाय-स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स के रूप में स्थापित किए जाएंगे।
- कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ।
- वस्त्र कौशल ईको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन।
- प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना।
- दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना है।
- आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में उच्च श्रेणी का 12 सप्ताह के प्रशिक्षण कोर्स द्वारा 20 महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए 10 हजार गाइडों के कौशल विकास हेतु पायलट योजना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया।

केंद्रीय बजट में राजस्थान को सौगात

नये अवसरों और प्रगति के साथ

> केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 'आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है।' इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
>
> **श्री भजनलाल शर्मा**, मुख्यमंत्री

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति केन्द्रित केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने वाले प्रावधान किए गए हैं, इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, 1 लाख 50 हजार केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को कौशल प्रशिक्षण से भी युवाओं को फायदा मिलेगा।

कंटेंट क्रियेटर लैब्स

प्रदेश में एवीजीसीएक्सआर पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है। अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रियेटर लैब्स की स्थापना से राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए सशक्तीकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, कृषि अवसंरचना एवं बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और जोखिम घटाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

निर्यात वृद्धि के अवसर

यूरोप के साथ ऐतिहासिक समझौता होने के बाद केंद्रीय बजट ने देश के छोटे-बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए नई दिशा दिखाई है। बायो फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्त्वपूर्ण पहल की गई हैं।

सोलर सेक्टर को मिलेगी नई गति

अक्षय ऊर्जा के लिए 30 प्रतिशत ज्यादा करीब 32 हजार 914 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार पीएम सूर्यघर योजना को 22 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोलर ग्लास मैन्युफेक्चरिंग में प्रयोग आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। बीईएसएस में उपयोग में आने वाले लीथियम आयन सेल बैटरी निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।

सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर प्रावधानों से प्रदेश होगा लाभान्वित

राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, एआईएमएल नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की हैं। इस क्रम में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए गए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉपअप छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात हैं।

इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को मजबूत करने का प्रयास

महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैम्पियन एमएसएमई बनाने की पहल से राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से मजबूत करने की घोषणा भी राजस्थान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

अवसंरचना विकास

बजट में अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए अधिक राशि मिल सकेगी। इनविट बॉन्डस, आरईआईटी और म्युनिसिपल बॉन्डस से मिलने वाले आर्थिक संबल से प्रदेश के शहर बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने जा रहे हैं।

पशुपालकों को भरपूर लाभ

वी बी-जी राम जी योजना में नरेगा की तुलना में 86 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 95 हजार 692 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। बजट में दी गई लोन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम का पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा।

ग्राम उत्थान शिविर

समृद्धि का सुनहरा प्रभात

नेमीचंद चौधरी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से राजस्थान में विकास का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। रेगिस्तान के विस्तृत विस्तारों से लेकर हरित वादियों तक अब ग्रामीण जीवन में भी नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो रहा है। उनकी प्रेरणादायी पहल के परिणामस्वरूप आयोजित ग्राम उत्थान शिविर न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम बने, बल्कि ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक सशक्त सेतु बनकर उभरे।

इन शिविरों के माध्यम से किसान, पशुपालक और आम ग्रामीण केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सीधे जुड़े और लाभान्वित हुए। प्रत्येक गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित इन शिविरों ने प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास, पारदर्शिता और संवाद का मजबूत आधार तैयार किया। यहां औपचारिकताओं की बजाए त्वरित एवं प्रभावी समाधान पर बल दिया गया, जिससे योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सका।

23 जनवरी (बसंत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

राज्य सरकार की 'जनसेवा ही सर्वोपरि' की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे शिविरों के प्रथम चरण में 31.57 लाख से अधिक ग्रामीणों ने

उत्साहपूर्वक भाग लिया। 13 प्रमुख विभागों—कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास आदि की योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे पहुंचा। इस दौरान मौके पर आवेदन तैयार हुए, लंबित मामलों की स्थिति बताई गई, पात्रों का पंजीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन किया गया। राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है- योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे। इसी क्रम में ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी तक वृहद रूप से आयोजित किया गया, ताकि और अधिक ग्रामीण सशक्त हो सकें।

पशुपालकों को सुखद अनुभव

कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में पशुपालक अपनी गाय-भैंस के साथ शिविर पहुंचता है और लौटते समय बीमा कवर, टीका और दवा सब साथ हो, यह कितना सुखद अनुभव होगा! यही कल्पना ग्राम उत्थान शिविर में साकार होती दिखी। इस बदलाव ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित हुई। इन पशुपालन राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ग्राम उत्थान शिविर इसे मजबूत बनाने का माध्यम बने। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 1.83 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किए गए। क्लासिकल स्वाइन फीवर हेतु 1.54 लाख से अधिक प्रतिरोधक टीकाकरण, 10,999 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान और 50,034 फर्टिलिटी किट वितरित हुए। साथ ही, 98,2696 पशुओं को प्राथमिक चिकित्सा और कृमिनाशक उपचार मिला।

किसानों की आय में स्थायी वृद्धि

राजस्थान में कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, उन्नत तकनीक और सरकारी सहयोग ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हुई और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हुई। ग्राम उत्थान शिविरों में कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि विपणन विभाग के माध्यम से 17.99 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की जानकारी दी गई, साथ ही 20.34 लाख से अधिक कृषकों को विविध योजनाओं की

जानकारी दी गई। 2,07,970 सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, जो मिट्टी की सेहत बताते हुए फसल उत्पादन बढ़ाने का मार्गदर्शन करेंगे। 6135 पॉली हाउस आवेदन तैयार हुए और मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के 3834 आवेदन निस्तारित किए गए। 3828 किसान विश्राम स्थल के निर्माण प्रस्ताव बने। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं, ये लाखों किसानों के स्वप्न हैं, जो अब हकीकत बन रहे हैं।

सहकारिता विभाग ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 56,089 किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन प्राप्त किए। लगभग 10,24,973 किसानों को सहकारी ऋण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही 10,209 कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन तैयार किए गए, 801 डेयरी सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं और उन्हें 1737 सरस बूथ एवं माट्स आवंटित किए गए। इन पहलों के माध्यम से किसान अब ऋण, गुणवत्तापूर्ण बीज और बाजार व्यवस्था से सीधे जुड़कर अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

ग्रामीण विकास का महायज्ञ

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आयोजित शिविर ऐतिहासिक सिद्ध हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 59,011 सर्वेक्षण पूर्ण किए गए तथा 86,522 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। 1711 अनुपयोगी विद्यालय भवनों में ग्राम पंचायत कार्यालय प्रारंभ कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त 7099 वाटर यूजर एसोसिएशन सक्रिय किए गए, 59,471 युवाओं के स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन प्राप्त हुए, 30,672 फार्मर रजिस्ट्रियां पंजीकृत की गईं, पीएम सूर्य घर योजनान्तर्गत 50,914 आवेदन पंजीकरण किए गए तथा 3915 भू-खसरा विभाजन हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से गांवों को ऊर्जा, जल संसाधन और रोजगार के अवसरों से सशक्त रूप से जोड़ा गया।

कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा और राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं, जिससे ग्रामीणों के समय, श्रम और संसाधनों की उल्लेखनीय बचत हुई। महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।

“भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारी सरकार गांवों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में लगाए गए ग्राम उत्थान शिविर सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है।”

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

कुल सहभागियों में 9,70,183 महिलाएं एवं 20,71,057 पुरुष, 31,843 जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में शामिल हुए। यह पहल दर्शाती है कि महिलाएं अब योजनाओं की प्रमुख हितग्राही और विकास प्रक्रिया की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

समृद्धि का संकल्प

ग्राम उत्थान शिविर केवल योजनाओं के वितरण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाधान, संवाद और सशक्तीकरण के सशक्त मंच के रूप में स्थापित हुए। इन शिविरों ने राजस्थान के ग्रामीण को आत्मनिर्भर, सक्षम और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया गया, जिससे आमजन का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हुआ।

यह पहल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। ग्रामीण भारत का स्वरूप बदल रहा है, जहां प्रत्येक गांव विकास और समृद्धि का प्रतीक बनकर उभर रहा है। इन शिविरों ने केवल योजनाओं का लाभ ही नहीं पहुंचाया, बल्कि आशा, विश्वास और सतत विकास की नई नींव रखी। राजस्थान ने इस मॉडल के माध्यम से ग्रामीण उत्थान का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम उत्थान शिविरों का अपने डीडवाना-कुचामन एवं रामगढ़ प्रवास के दौरान अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा पात्र लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंच सके।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

समावेशी विकास की सुदृढ़ नींव

हेत प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक

विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी और मानवाधिकारों के हनन जैसी सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस समाज में सभी के लिए समानता, समावेश और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राज्य की सामाजिक नीति का आधार स्तंभ माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभाग की कार्यप्रणाली राज्य की उस नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, जिसके अंतर्गत विकास के लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। विभाग केवल कल्याणकारी योजनाओं का संचालन नहीं करता, बल्कि सामाजिक असमानताओं को संरचनात्मक स्तर पर संबोधित करते हुए समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन की संवैधानिक अवधारणा को मूर्त रूप देता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सुदृढ़ व्यवस्था की रीढ़ हैं। वर्तमान में लगभग 91.83 लाख लोग इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत वृद्धावस्था, विधवा या एकलनारी, दिव्यांगजन तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी तथा फरवरी 2026 से देय होगी।

छात्रवृत्ति योजना

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग सहित वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ रही हैं। योजना के माध्यम से न केवल शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों के लिए समान अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

सुधारों का नीतिगत महत्व

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में डीबीटी आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाकर विभाग ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को संस्थागत रूप दिया है। वर्तमान में भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में किया

जा रहा है, जिससे अनियमितताओं, विलंब और शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राज्य सरकार की सामाजिक न्याय आधारित शिक्षा नीति का एक सशक्त स्तंभ है। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, रेलवे एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे संसाधनों के अभाव में दबे प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का ठोस अवसर मिल रहा है और सामाजिक समावेशन को नई दिशा मिल रही है। हर वर्ष प्रदेश के लगभग 30 हजार छात्र-छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

देवनारायण योजना

जस्टिस चोपड़ा कमेटी की सिफारिशों के तहत में प्रारंभ की गई देवनारायण योजना ने अति पिछड़ा वर्ग के विकास की दिशा को संरचनात्मक रूप से बदल दिया है। प्रारंभ में 5 जिलों की 13 तहसीलों तक सीमित यह योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, जिससे इसका लाभ व्यापक स्तर पर पहुंच सका। शिक्षा को केंद्र में रखकर संचालित इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में 395.68 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले दिसंबर 2025 तक 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर मैट्रिक और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता मिली, जबकि देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत नींव रखी गई। समग्र रूप से यह योजना अति पिछड़ा वर्ग के लिए केवल एक कल्याणकारी पहल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की प्रभावी नीति के रूप में स्थापित हुई है।

शिक्षा आधारित योजनाएं

छात्रवृत्ति और छात्रावास योजनाएं वंचित वर्गों के लिए सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख साधन बनकर उभरी हैं। प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा की निरंतरता मिली है, जिससे पीढ़ीगत पिछड़ेपन को तोड़ने में मदद मिली है।

नशा मुक्ति

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील मार्गदर्शन में विभाग द्वारा उन युवाओं का हाथ थाम रहे हैं, जिन्होंने नशे की गिरफ्त में अपना सब कुछ लगभग खो दिया था। प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति केंद्र आज सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि उन परिवारों की उम्मीद हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को खोने का डर देखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में 82 लाइसेंसशुदा गैर-अनुदानित, 10 राज्य सरकार द्वारा अनुदानित और 38 भारत सरकार द्वारा अनुदानित नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट सोच है कि राजस्थान का कोई भी युवा नशे की लत से अकेला न लड़े। इसी भावना के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए। आज ये केंद्र पूरी क्षमता से संचालित हैं और सैकड़ों युवा नशे से बाहर निकलकर फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

पालनहार योजना

पालनहार योजना का उद्देश्य अनाथ एवं संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में शिक्षा और पालन-पोषण उपलब्ध कराना है। इस योजना में अनाथ बच्चे, विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चे, जेल में बंद माता-पिता के बच्चे, गंभीर रोगों या HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं के बच्चे, लावारिस या परित्यक्त बच्चे तथा विशेष योग्यजन के बच्चे शामिल हैं। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए तथा 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 750 रुपए तथा 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री के सुशासन में संचालित यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि 'डिजिटल सुशासन' के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था की मिसाल भी पेश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में वर्ष 2023-24 से अब तक 14261.86 लाख रुपए व्यय कर 34 हजार 704 कन्याओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

योजना के तहत SC, ST एवं अल्पसंख्यक (BPL परिवार) को विवाह पर 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। शेष सभी बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित कन्याओं और महिलाओं को 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यही नहीं विभाग द्वारा बेटियों को शिक्षा के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देय है। यदि बेटी 10वीं पास है, तो 10 हजार रुपए और यदि स्नातक है तो 20 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है।

दिव्यांगजनों के लिए नीतियां

विभाग की नीतियां दिव्यांगजनों को कल्याण का विषय नहीं, बल्कि अधिकारों के सहभागी के रूप में स्थापित करती हैं। दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से दिव्यांगजन आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।

दीर्घकालीन विकास में भूमिका

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दीर्घकालीन और दूरदर्शी सोच से विभाग समावेशी विकास की नींव रख रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और कोई भी नागरिक विकास प्रक्रिया से वंचित न रहे।

जयपुर एयर शो

जयपुर में जलमहल की पाल पर भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने रोमांचक करतबों से जयपुरवासियों और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खुले आसमान में सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सारंग स्पिलिट, एरोहैड, डॉल्फिन लीप, लेवल क्रॉस, हाई स्पीड क्रॉस, क्रॉस ओवर ब्रेक, डायमंड एवं इन्वर्टेड वाइन ग्लास जैसी अनेक आकृतियां बनाईं। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने इन्वर्टेड रन, बैरल रोल, बॉम्ब बर्स्ट, डीएनए संरचना जैसी अनेक आकृतियों के साथ आसमान में दिल बनाकर वायु सेना की ओर से जयपुरवासियों का अभिनंदन किया।

मरु महोत्सव-2026

जीवंत राजस्थान की पहचान

रेत, राग और रोमांच

प्रवीण प्रकाश, जनसम्पर्क अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध लोकसंस्कृति एवं रंगीन परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के साथ-साथ यहां के मेले एवं उत्सवों को प्रोत्साहन देने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इसी सोच को साकार करते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेशभर में विविध सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिनमें जैसलमेर का विश्वविख्यात मरु महोत्सव-2026 विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। 29 जनवरी से 01 फरवरी 2026 तक आयोजित इस चार दिवसीय सांस्कृतिक महाकुंभ ने मरुधरा की आत्मा, लोकजीवन की जीवंतता और राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। पोकरण, जैसलमेर, सम-लखमणा और खुहड़ी के रेतीले धोरों पर आयोजित इस ऐतिहासिक महोत्सव में देश-विदेश से आए पर्यटकों एवं कला प्रेमियों ने राजस्थान की संस्कृति, लोकपरंपराओं और मनोरंजन का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। लोक एवं सैलिब्रिटी कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां, पारंपरिक प्रतियोगिताएं, कैमल शो, लोकनृत्य, हस्तशिल्प मेले एवं सांस्कृतिक संध्याओं ने आयोजन को भव्यता प्रदान की।

प्रदेश की गौरवशाली परम्पराएं जीवन्त

31 जनवरी को आयोजित कार्यक्रमों में योग एवं लोकवाद्य संगीत, बीएसएफ कैमल टेंटू शो, एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल, ग्रामीण खेलकूद, कैमल पोलो एवं ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता आदि विशेष आकर्षण रहे। 'शान-ए-मरुधरा' जैसे कार्यक्रमों ने राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन किया।

मिस व मिस्टर पोकरण और ग्रामीण खेलों की लोक रंगत

महोत्सव का शुभारंभ 29 जनवरी को परमाणु नगरी पोकरण में नेपालेश्वर महादेव मंदिर में आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात पोकरण फोर्ट से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। मिस व मिस्टर पोकरण प्रतियोगिता, ग्रामीण खेलकूद एवं रस्साकस्सी जैसे कार्यक्रमों ने ग्रामीण संस्कृति की झलक प्रस्तुत की।

खुहड़ी के धोरों पर चांदनी रात में ऐतिहासिक समापन

01 फरवरी को पहली बार माघ पूर्णिमा की चांदनी रात में खुहड़ी के रेतीले धोरों पर महोत्सव का भव्य समापन हुआ। घुड़दौड़, मांडणा कला प्रदर्शनी, कैमल रेस एवं इंडियन आइडल फेम पियूष पंवार की शानदार प्रस्तुति इस अवसर के मुख्य आकर्षण रहे। मरुधरा की रेत पर सजी रंगीन प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया।

पर्यटन और संस्कृति को मिला वैश्विक मंच

मरु महोत्सव-2026 ने राजस्थान की लोकसंस्कृति, परंपरा, संगीत और पर्यटन की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन न केवल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर प्रदर्शित करता है, बल्कि स्थानीय कलाकारों, हस्तशिल्पकारों एवं पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा प्रदान करता है।

राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों एवं प्रभावी आयोजन के माध्यम से जैसलमेर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान बनाने में सफल रहा। मरु महोत्सव-2026 ने यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की रंगीन संस्कृति, लोकजीवन की विविधता और मरुधरा की अद्वितीय पहचान देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहेगी।

साफा बांधो और मूंछ प्रतियोगिता

30 जनवरी को सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में आरती के साथ जैसलमेर नगर में महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हुआ। गड़ीसर झील से शहीद पूनमसिंह स्टेडियम तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान मरुश्री, मिस मूमल-2026, मिसेज जैसलमेर, साफा बांधो एवं मूंछ प्रतियोगिता जैसी पारंपरिक गतिविधियों ने आयोजन को जीवंत बनाया। साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट मेला, पपेट शो एवं फूड फेस्टिवल ने पर्यटकों को राजस्थान की विविधता से रूबरू कराया। सायंकाल प्रसिद्ध बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मधुबंती बागची की प्रस्तुति ने सांस्कृतिक संध्या को नई ऊंचाई प्रदान की।

Pariksha Pe Charcha 2026

विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की सीख

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कक्षा 10वीं और 12वीं सहित विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा जीवन की महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है, अतः विद्यार्थी तनावमुक्त रहकर परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ परीक्षा दें तथा अभिभावक घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विद्यार्थियों को दिए शिक्षा और जीवन में

सफलता के मूलमंत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें संस्करण के अंतर्गत विद्यार्थियों से संवाद करते हुए परीक्षा को उत्सव की तरह लेने, आत्मविश्वास और अनुशासन बनाए रखने, निरंतर अभ्यास करने तथा स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली और विकसित भारत के संकल्प जैसे विषयों पर भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

- सबसे पहले अपनी रुचि और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह प्रौद्योगिकी में नवाचार हो, ड्रोन का विकास हो या विद्युत प्रणालियों जैसे व्यावहारिक समाधान।
- पढ़ाई और शौक दोनों ही उपयोगी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं।
- छात्रों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए और विषय पर पूरी तरह से पकड़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- सफलता के लिए प्रेरणा और अनुशासन दोनों ही आवश्यक हैं।
- तकनीक को समझना, अपनी क्षमताओं का विस्तार करना और उसकी खूबियों को कार्य में बिना किसी भय के जोड़ना प्रगति सुनिश्चित करता है।
- सच्ची शक्ति शिक्षा और खेल दोनों में निपुण होने में निहित है।
- नेतृत्व तब शुरू होता है, जब कोई दूसरों का इंतजार किए बिना कार्य करने का निर्णय लेता है।
- आत्मविश्वास दो शब्दों- "आत्मा" और "विश्वास" से आता है, जिसका अर्थ है स्वयं पर विश्वास। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वे कभी नहीं डरते और वे कार्य करने से पहले स्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं।

प्रतिस्पर्धा को हावी नहीं होने दें

मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी पर आयोजित मेगा पीटीएम में विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा को खुद पर हावी नहीं होने दें, हमारी असली प्रतिस्पर्धा खुद से होनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए जिससे वे भविष्य में ऊंची उड़ान भर सकें।

युवा जोश, हरित संदेश और विकास का विज़न

अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन

राजस्थान में विकास की परिकल्पना अब केवल आधारभूत ढांचे और योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तीकरण और पर्यटन संवर्धन जैसे व्यापक आयामों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इसी दूरदर्शी सोच का सशक्त उदाहरण अलवर में आयोजित अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन के रूप में सामने आया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन ने यह संदेश दिया कि राज्य सरकार स्वस्थ, जागरूक और सहभागी राजस्थान के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह आयोजन खेल, सामाजिक चेतना और प्रकृति संरक्षण का साझा मंच बन गया...

रोहताश सिंह यादव, वित्तीय सलाहकार

नेतृत्व की उपस्थिति ने बढ़ाया विश्वास और उत्साह

सुबह की हल्की सर्द हवाओं के बीच हजारों प्रतिभागियों की मौजूदगी ने वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा के साथ विभिन्न श्रेणियों की मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मैराथन के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता श्री रणदीप हुड्डा की उपस्थिति ने युवाओं के आकर्षण और भागीदारी को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रतिभागियों से संवाद किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया और युवाओं के साथ सेल्फी लेकर उनका उत्साह बढ़ाया। यह आयोजन नेतृत्व और जनभागीदारी के सहज जुड़ाव का प्रतीक रहा।

हर वर्ग के लिए अवसर

मैराथन को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि हर स्तर के धावक इसमें भाग ले सकें। आयोजन के अंतर्गत 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एलीट पुरुष एवं महिला वर्ग, 21 किलोमीटर फोर्स रन, 21 किलोमीटर ओपन हाफ मैराथन

तथा 10 किलोमीटर ओपन मैराथन का आयोजन किया गया। विभिन्न देशों के धावकों के साथ-साथ सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी इसमें भाग लेकर आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 21 किलोमीटर एलीट पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेताओं का फिनिश लाइन पर हौसला बढ़ाया।

फिट इंडिया, टाइगर संरक्षण और पर्यटन को नई दिशा

यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की मैराथन अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसकी थीम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल 'फिट इंडिया मिशन', टाइगर संरक्षण और अलवर पर्यटन को प्रोत्साहन देने से जुड़ी थी। राज्य सरकार की नीतियों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और साथ ही वन्यजीव संरक्षण एवं प्राकृतिक धरोहरों के प्रति जनजागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। सरिस्का और अलवर क्षेत्र की पहचान टाइगर संरक्षण से जुड़ी है, ऐसे में मैराथन जैसे आयोजन से संरक्षण संदेश को जनआंदोलन का रूप देने की पहल प्रभावी साबित हो रही है।

जनभागीदारी ने बनाया खेल को जन-उत्सव

आयोजन के दौरान जनसहभागिता का उत्साह उल्लेखनीय रहा। शहरवासियों और युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने पूरे कार्यक्रम को उत्सव जैसा स्वरूप प्रदान किया। यह आयोजन दर्शाता है कि राज्य सरकार खेल गतिविधियों को सामाजिक अभियान का रूप देने की दिशा में कार्य कर रही है, जहां भागीदारी, प्रेरणा और सामूहिक ऊर्जा प्रमुख तत्व हैं।

खेल के साथ संस्कृति का सम्मान

राजस्थान सरकार की विकास दृष्टि में संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी समान रूप से शामिल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने पद्म श्री विजेता भपंग वादक श्री गफरूद्दीन मेवाती जोगी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। खेल आयोजन के मंच से लोक कलाकार का सम्मान यह दर्शाता है कि राज्य में आधुनिकता और परंपरा साथ-साथ आगे बढ़ रही है।

स्वस्थ और जागरूक राजस्थान की ओर सतत पहल

वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और पर्यावरणीय दबाव को देखते हुए ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। राज्य सरकार द्वारा निरंतर ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन इसी सतत, संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरी है। जहां दौड़ केवल लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं, बल्कि सशक्त और स्वस्थ राजस्थान के निर्माण की प्रतीक बन गई।

रेडियो
समुदाय, संस्कृति और संचार का सेतु

अमन हरसाना, स्वतंत्र लेखक

मानव सभ्यता के इतिहास में संचार के साधनों ने समाज को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो का आविष्कार इसी परिवर्तनकारी यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव रहा है। आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) युग के आगमन से बहुत पहले रेडियो का अपना एक अनोखा आकर्षण रहा है। यह वह भरोसेमंद आवाज थी, जो दूर-दराज के इलाकों, विविध भाषाओं और अनगिनत जिंदगियों को एक अदृश्य धागे में पिरोती थी। रेडियो के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से 'फादर ऑफ़ रेडियो' कहे जाने वाले गुग्लिएल्मो मारकोनी को दिया जाता है, जिन्होंने 1895 में वायरलेस संचार का सफल प्रदर्शन किया।

विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो (UN Radio) की स्थापना की स्मृति का प्रतीक है। विश्व रेडियो दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 2011 में अपने 36वें आम सम्मेलन के दौरान की थी। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें सत्र में आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम - "रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई एक उपकरण है, आवाज़ नहीं।" रही है।

यह थीम प्रसारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर केंद्रित है, साथ ही यह भी रेखांकित करती है कि संपादकीय विवेक, विश्वसनीयता और मानव आवाज़ रेडियो के मूल में बने रहने चाहिए। इस विषय के अंतर्गत यह बताया गया है कि एआई सामग्री निर्माण, अभिलेखीकरण, अनुवाद, श्रोता सहभागिता और पहुंच बढ़ाने में सहायक हो सकता है, परंतु इसका उपयोग नैतिक और संतुलित होना चाहिए ताकि तकनीक रेडियो के मूल्यों को सशक्त बनाए, प्रतिस्थापित नहीं करे।

आज़ादी की गूंज: रेडियो तरंगों पर नया भारत

14–15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक मध्यरात्रि, जो आज भी भारत की सामूहिक स्मृति में अमिट रूप से अंकित है, जब स्वतंत्रता की घोषणा रेडियो तरंगों पर गूंज उठी थी। उस क्षण रेडियो केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रहा, बल्कि वह नवजागृत राष्ट्र की धड़कन बन गया। लाखों भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्र भारत की आवाज़ रेडियो के माध्यम से ही सुनी। उस एक प्रसारण ने केवल सूचना का संचार ही नहीं किया, बल्कि एक विशाल, बहुभाषी और विविधतापूर्ण देश को स्वतंत्रता की साझा अनुभूति में एकसूत्र में बांध दिया।

आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के नाम से भी जाना जाता है, प्रसार भारती के अंतर्गत भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसका आदर्श वाक्य है - "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।" वर्ष 1936 में स्थापित और स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक स्वामित्व में लाया गया ऑल इंडिया रेडियो, प्रसारित भाषाओं की संख्या तथा श्रोताओं की विविधता के मामले में विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है।

आज आकाशवाणी (एआईआर) की होम सर्विस देशभर में फैले 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है, जो भारत के लगभग 92 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 99.19 प्रतिशत जनसंख्या को आच्छादित करती है। स्थलीय प्रसारण के जरिए यह 23 भाषाओं और 182 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, जो भारत की व्यापक सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विविधता का सजीव प्रतिबिंब है।

सामुदायिक रेडियो: जहां हर आवाज़ को मिलता है मंच

सामुदायिक रेडियो एक ऐसा मंच जो सच मायनों में स्थानीय समाज की धड़कन बनकर उभरा है, जहां गांव की चौपाल, खेत की मेड़, स्कूल का प्रांगण

और स्वयं सहायता समूह की बैठक सबकी आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। भारत में इसकी औपचारिक यात्रा वर्ष 2002 में आरंभ हुई, जब भारत सरकार ने आईआईटी, आईआईएम सहित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्थापित करने की अनुमति दी।

1 फरवरी 2004 को तात्कालिक सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत रत्न श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन इस दिशा में ऐतिहासिक कदम था। देश में सामुदायिक रेडियो के जनक माने जाने वाले डॉ. श्रीधर राममूर्ति ने देश का पहला परिसर-आधारित (कैंपस) सामुदायिक रेडियो स्टेशन "अन्ना एफएम" की शुरुआत कर इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी।

वर्ष 2005 में राजस्थान के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन "अपनो रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज" की शुरुआत हुई, जो टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ द्वारा संचालित किया जाता है। वही 2008 में दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया संगम रेडियो देश का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाने वाला सामुदायिक रेडियो स्टेशन बना।

जनवरी 2026 में भारतीय सेना और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के राजौरी में "रेडियो संगम 88.8 एफएम" का शुभारंभ किया। यह नियंत्रण रेखा के साथ स्थित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, जिसका उद्देश्य सत्यापित जानकारी को बढ़ावा देना और सीमा पार के दुष्प्रचार का मुकाबला करना है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज देशभर में 528 सामुदायिक रेडियो स्टेशन सक्रिय हैं, जो जमीनी स्तर पर सूचना, सहभागिता और सशक्तीकरण की नई कहानियां लिख रहे हैं।

डिजिटल युग में रेडियो की शक्ति को सुदृढ़ करती 'मन की बात'

डिजिटल व सोशल मीडिया के प्रभुत्व वाले इस युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से सीधे संवाद के प्राथमिक माध्यम के रूप में रेडियो का चयन इसकी स्थायी प्रासंगिकता और उससे जुड़े भरोसे को रेखांकित करता है। 3 अक्टूबर 2014 को सदी के सबसे बड़े सहभागी संचार के तौर पर शुरू हुआ 'मन की बात' ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जो 22 भारतीय बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट के जरिये 100 करोड़ से अधिक श्रोताओं को जोड़ता है। कार्यक्रम ने फरवरी, 2026 तक कुल 130 एपिसोड के माध्यम से फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स अर्जित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 'मन की बात' के शताब्दी एपिसोड का लाइव प्रसारण दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है।

भारत में रेडियो का इतिहास

- 1923 – बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा पहला रेडियो प्रसारण।
- 1927 – 23 जुलाई को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) की स्थापना, जिसे अब राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 1930 – इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (ISBS) की शुरुआत।
- 1935 – आकाशवाणी मैसूर नामक देश के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना।
- 1936 – इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया।
- 1942 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा जर्मनी में "आजाद हिंद रेडियो" की स्थापना।
- 1947 – स्वतंत्रता के समय भारत में AIR के छह (दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ) रेडियो स्टेशन थे।
- 1947 – 12 नवंबर को महात्मा गांधीजी ने अपना पहला और एकमात्र रेडियो संदेश दिया।
- 1956 – AIR का आधिकारिक नाम "आकाशवाणी" रखा गया। जिस का अर्थ "आकाश से आने वाली आवाज़" हैं। यह नाम रवीन्द्रनाथ टैगोर की 1938 में लिखी एक कविता के शीर्षक से प्रेरित था, जिसे कोलकाता के पहले शॉर्ट-वेव रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के लिए लिखा गया था।
- 1957 – विविध भारती सेवा का शुभारंभ।
- 1969 – दिल्ली से 'युव-वाणी' सेवा की शुरुआत।
- 1977 – मद्रास (चेन्नई) से पहली एफएम सेवा का उद्घाटन।
- 1997 – प्रसार भारती निगम अस्तित्व में आया।
- 2000 – शैक्षिक एफएम रेडियो चैनल 'ज्ञान वाणी' की शुरुआत।
- 2004 – AIR और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा का उद्घाटन।
- 2011 – एफएम गोल्ड ने 24 घंटे की सेवा शुरू की।
- 2012–बांग्लादेश ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में योगदान के लिए आकाशवाणी को मान्यता दी।
- 2015 – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का "मन की बात" कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और AIR पर एक महत्त्वपूर्ण मंच बन गया।
- 2016 – AIR ने नई सेवा "AIR लाइव न्यूज 24x7" शुरू की, जो निरंतर समाचार कवरेज प्रदान करती है।
- 2017 – AIR ने अपने कार्यक्रमों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल लॉन्च किया।
- 2023 – 30 अप्रैल को 'मन की बात' ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे किए।

युवा बनें रोजगारदाता

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से नई शुरुआत

डॉ. सूरज कुमार बैरवा, जनसंम्पर्क अधिकारी

राजस्थान का युवा नौकरी लेने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बनें और राजस्थान को विकसित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसी सोच को साकार रूप देने की दिशा में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' लागू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण दिलाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क का पुनर्भरण किया जा रहा है। इससे प्रदेश में युवा स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और स्वरोजगार का एक नया ईको-सिस्टम विकसित होगा। साथ ही, अन्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रोत्साहन में मील का पत्थर

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्योग शुरू करने वाले युवाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। इस योजना में उद्योग स्थापना के दौरान आने वाली कठिनाइयों को ध्यान रखते हुए अहम प्रावधान किए गए हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, इसलिए इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण दिलवाने का प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही, स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि उद्योग शुरू करने में लगने वाली राशि और ऋण राशि के बीच के अंतर को पाटने के लिए 50 हजार रुपए तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क का पुनर्भरण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के विशेष प्रावधानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

विस्तृत गाइडलाइन जारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी

कर 22 जनवरी से आवदेन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 16 फरवरी तक 15 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया। राज्य बजट वर्ष 2026-27 में इस योजना के तहत 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के तहत देय लाभ

8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए योजना में 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया

एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)' आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।

इसके बाद आवेदक को अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा।

> "'समर्थ युवा, विकसित राजस्थान' के विज़न के अनुरूप हमारी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार के बल पर प्रदेश को प्रगति के नए शिखर तक पहुंचाएंगे।"
>
> **मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेजा जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज।

पात्रता

आवेदक राजस्थान के मूल निवासी व आयु 18-45 वर्ष हो। एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक एवं संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य है।

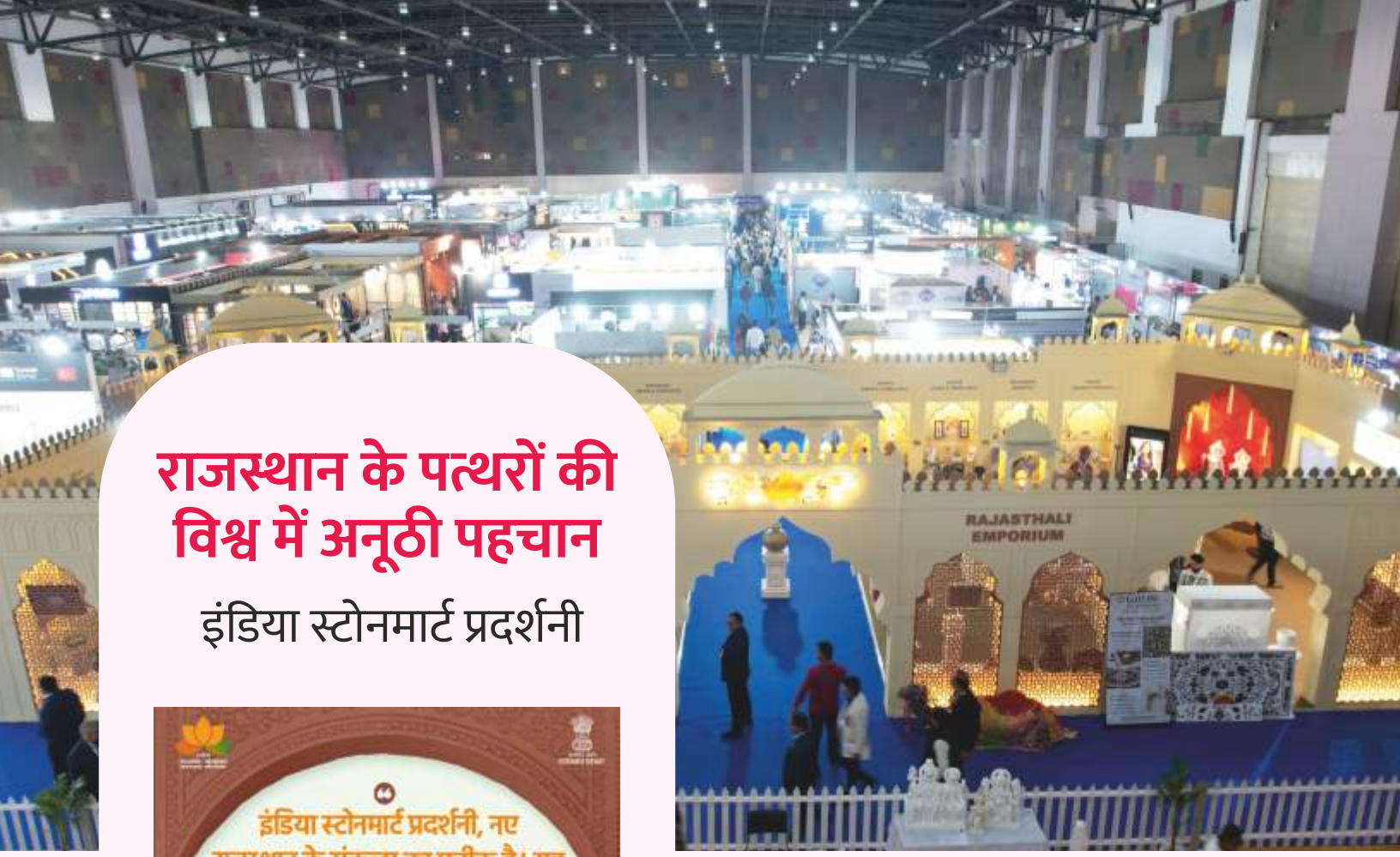

राजस्थान के पत्थरों की विश्व में अनूठी पहचान

इंडिया स्टोनमार्ट प्रदर्शनी

राजस्थान के पत्थरों की विशिष्टता की विश्व पटल पर अनूठी पहचान है। देशभर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों, किलों, महलों में राजस्थान का पत्थर उपयोग में लाया गया है। अब राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा राज्य सरकार इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर एग्ज़ीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में 5 से 8 फरवरी तक 13 वें इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का सफल आयोजन किया गया। राजस्थान के पत्थर क्षेत्र में कारोबारी इजाफे के रूप में एग्जीबीटर्स को अहम ऑर्डर मिले। चार दिन की स्टोन मार्ट प्रदर्शनी में मौके पर 3200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव मिले। प्रदर्शनी में 27,256 विजिटर्स ने दौरा किया। यूनिक विजिटर्स की संख्या इस बार सबसे अधिक रही। पहली बार फिजिकल मीटिंग के साथ स्टोनमार्ट मोबाइल एप पर बीटूबी मीटिंग्स भी आयोजित हुई।

8 देशों के बायर्स के लिए कारोबारी संभावना

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप नीतिगत पहल, रोजगार संभावनाओं, तकनीक के उपयोग और आर्टिजन हितैषी कदम इस आयोजन में दिखे। प्राकृतिक पत्थर उद्योग के इस अंतरराष्ट्रीय मेले ने भागीदारी, क्षेत्रफल और वैश्विक उपस्थिति के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस बार कुल 496 प्रदर्शकों ने भाग लिया। यह अब तक आयोजित स्टोन मार्ट में सर्वाधिक रहा। जिनमें से 8 देशों चीन, तुर्की, ईरान, इटली, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड और स्पेन से 59 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शक शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी में 26 चीनी और 21 तुर्की कंपनियां प्रमुख रहीं। इटली की तीन और ईरान की पांच कंपनियों ने भी राजस्थान के पत्थर में कारोबारी भविष्य तलाशा।

अब तक के सबसे बड़े क्षेत्र में आयोजन

13वां इंडिया स्टोनमार्ट 2026 अब तक के सबसे बड़े क्षेत्र में आयोजित हुआ। इंडिया स्टोनमार्ट 2026 की प्रदर्शनी में कुल 21,917 वर्गमीटर क्षेत्र में 496 स्टॉल बुक हुए। आयोजक संस्था सिडॉस और लघु उद्योग भारती ने नियोजित क्षेत्र 23,431 वर्गमीटर रखा था। जयपुर में आयोजित स्टोनमार्ट के

इस संस्करण में इंडोर हॉल में 14,117 वर्गमीटर में 440 स्टॉल लगाई गई, वहीं आउटडोर में 6,800 वर्गमीटर क्षेत्र में 56 स्टॉल को जगह दी गई। इस बार का विशिष्ट आकर्षण पत्थरों का आध्यात्म में महत्व भी रहा। आर्ट गैलरी अक्षरधाम के लिए 900 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई। इसके अलावा टूल्स एवं मशीनरी सेक्शन में 238 तथा ऑर्गनाइजेशन एंड सर्विस रिलेटेड सेक्शन में 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

राज्यों की भागीदारी से बढ़ा उत्साह

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 में देश के 15 राज्यों ने भाग लिया। स्टोनमार्ट 2026 में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और तमिलनाडू की भागीदारी रही। राजस्थान के विभिन्न विभागों के पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र रहे। यहां पर राजस्थान सरकार की योजनाओं का हाथों हाथ लाभ निवेशकों और विजिटर्स को मिला। इस आर्टिस्ट पवेलियन में 255 वर्गमीटर क्षेत्र में 50 कलाकारों ने प्रदर्शक के रूप में हिस्सा लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा शिल्पी प्रतिनिधित्व रहा।

जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल से मिली आधुनिक दिशा

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 में दो दिन जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ। इसमें 400 राष्ट्रीय और 10 अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट्स की मौजूदगी रही। स्टोन इंडस्ट्री में नवाचार कर रहे स्टूडेंट्स को भी इसमें भागीदारी का मौका मिला। आर्किटेक्ट्स की भागीदारी ने आयोजन को और अधिक पेशेवर आयाम दिया। इंडिया स्टोनमार्ट 2026 ने एक बार फिर साबित किया कि राजस्थान न केवल सांस्कृतिक विरासत, बल्कि प्राकृतिक पत्थर उद्योग के वैश्विक केंद्र के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

डिजिटल इंडिया का ‘भारत विस्तार’

कृषि क्षेत्र में नई उड़ान

अम्बिका शर्मा, स्वतंत्र लेखिका

जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने AI आधारित कृषक सूचना प्रणाली ‘भारत विस्तार’ का शुभारंभ करते हुए कृषि में डिजिटल क्रांति का शंखनाद किया। इस प्लेटफॉर्म से किसानों को उनकी खेती से जुड़ी विविध जानकारियां सही समय पर मिल सकेंगी। देशभर में शुरू हुए इस एआई आधारित नवाचार से किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समग्र कृषि सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता को बल मिलेगा एवं किसान सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनेंगे।

एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारियां

भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को रियल टाइम मंडी मूल्य, भारतीय कृषि शोध संस्थान की कृषि पद्धतियां, केन्द्र की कृषि संबंधी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, फसल आधारित वैज्ञानिक परामर्श, मौसम पूर्वानुमान, कृषि ऋण, सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन सहित तमाम जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल पाएंगी। वर्तमान में यह सेवा हिन्दी एवं इंग्लिश में शुरू की गई हैं तथा भविष्य में यह 11 अन्य भाषाओं में भी शुरू होगी। साथ ही, इस प्लेटफॉर्म को एग्रीस्टैक से भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत किसान फार्मर आई.डी. के माध्यम से खेत से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।

कृषक कल्याण के लिए हो रहे निरंतर कार्य

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती को तरफ बढ़ावा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, किसानों को खेती के साथ पशुपालन एवं कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहन सहित अनेक निर्णय लिए गए हैं। जिससे देश का अन्नदाता लाभान्वित हो रहा है।

155261 नम्बर पर मिलेगा समाधान

भारत विस्तार योजना के अंतर्गत किसान 155261 नंबर पर डायल कर अपनी समस्या बता सकेगा और उसे तुरंत उसका समाधान मिलेगा। इसी नंबर

से देशभर की विभिन्न मंडियों का बाजार भाव भी पता लगाया जा सकता है।

सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान देश में प्रथम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के ने इस अवसर पर कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वह राष्ट्र की नींव है। हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें, तो निश्चित उसकी आय बढ़ेगी, जिससे देश का विकास होगा। हमें कृषि को आगामी पीढ़ी के लिए संजोकर रखना चाहिए। अधिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मृदा खराब होती है। इसलिए यह जरूरी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही आवश्यकतानुसार खाद एवं कीटनाशक का उपयोग हो। राजस्थान में 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा मरुस्थल का है। राज्य सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे नवाचारों का परिणाम है कि सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

ए.आई. के माध्यम से लागू होने वाली प्रणाली भारत विस्तार कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। केन्द्र सरकार ने आधार, यूपीआई और एग्रीस्टेक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में ए.आई. पर आधारित यह राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। यह एक ऐसा तकनीकी बदलाव है, जहां तकनीक, ज्ञान और किसान एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तार के माध्यम से किसानों के फोन में फसल की योजना, खेती के बेहतर तरीके, कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्यपालन, पशुपालन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश के किसानों को भी व्यापक फायदा मिलेगा।

किसानों तक सेवाओं की पहुंच होगी सरल

महाराष्ट्र से महाविस्तार, बिहार से बिहार कृषि, और गुजरात से अमूल जैसे सिस्टम पहले ही इससे जुड़ चुके हैं। यह एक साझा डिजिटल आधार है, जो केंद्र और राज्यों की प्रणालियों को जोड़कर किसानों तक सेवाएं सरल, एकीकृत और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाने का माध्यम बनेगा।

प्रदेश पहले स्थान पर

प्रदेश बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है। गेहूं की खरीद पर बोनस, 50 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 18 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन तथा 63 हजार से अधिक सोलर पंप जैसे निर्णयों से प्रदेश में किसान सशक्त हुए हैं।

भारत का स्वास्थ्य दर्शन और आयुर्वेद की वैश्विक पहचान

आकांक्षा शर्मा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

हजारों वर्ष पूर्व चरक संहिता में कहा गया - "पुरुषोऽयं लोकसम्मितः", अर्थात् मनुष्य स्वयं प्रकृति का प्रतिबिंब है। आयुर्वेद इसी दर्शन पर आधारित वह ज्ञान परंपरा है, जो शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन को स्वास्थ्य का मूल मानती है। "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम" की भावना को आत्मसात करते हुए आयुर्वेद केवल उपचार का विज्ञान नहीं, बल्कि विश्वकल्याण की जीवनशैली का संदेश देता है। बदलती जीवनशैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच, यह प्राचीन ज्ञान आज फिर आधुनिक दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है।

आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ और प्रकृति के अनुरूप रखने का विज्ञान है। इसी समग्र दृष्टि ने आयुर्वेद को हजारों वर्षों से भारत की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि भारत की चिकित्सा पद्धति शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। 'भारत में उपचार और भारत द्वारा उपचार' पर आधारित आयुष प्रणाली को वैश्विक मंच पर स्थापित करना उनका संकल्प है। आयुष मंत्रालय की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक मान्यता और आयुर्वेद अनुसंधान में बढ़ते निवेश इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

राजस्थान की माटी - आयुर्वेद की प्राकृतिक प्रयोगशाला

राजस्थान की भौगोलिक विविधता, पहाड़ी क्षेत्र, वन संपदा और औषधीय वनस्पतियां इस प्रदेश को आयुर्वेद के लिए विशेष बनाती हैं। यहां की मिट्टी में औषधीय पौधों की अपार संभावनाएं हैं, जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सदियों से पोषित किया है। आयुर्वेद यहां केवल चिकित्सकीय प्रणाली नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा है, जो खान-पान, दिनचर्या और लोक परंपराओं में सहज रूप से दिखाई देता है। बदलती जीवनशैली और आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच आयुर्वेद आज पुनः प्राकृतिक, सुरक्षित और संतुलित विकल्प के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान - शिक्षा, अनुसंधान और सेवा का केंद्र

जयपुर स्थित National Institute of Ayurveda (NIA) आज देश में आयुर्वेद शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान का प्रमुख संस्थान बन चुका है। एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ हुआ यह संस्थान अब डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होकर शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा-इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित कर चुका है। आधुनिक प्रयोगशालाएं, पंचकर्म इकाइयां, शोध आधारित शिक्षा और क्लीनिकल सेवाएं इसे परंपरा और आधुनिक विज्ञान के संगम का प्रतीक बनाती हैं। यहां विकसित हो रहा आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर औषधीय पौधों की डीएनए बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और गुणवत्ता परीक्षण जैसे उन्नत कार्यों के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

वैज्ञानिक प्रमाणिकता की ओर प्रयास

जयपुर में विकसित हो रहा आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर आयुर्वेद को 'आस्था आधारित चिकित्सा' से 'प्रमाण आधारित चिकित्सा' की दिशा में ले जाने वाला ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत डीएनए बैंक और डाटा बेस की स्थापना, औषधियों का वैज्ञानिक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इससे न केवल औषधीय उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों, हर्बल उद्योग और वेलनेस टूरिज्म के लिए भी नए अवसर खुलेंगे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को नई ऊर्जा

राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और औषधीय परंपराओं से समृद्ध धरती पर आयुर्वेद केवल उपचार पद्धति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और समग्र दृष्टि से देखने का दर्शन रहा है। इसी गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के मंच से आयुर्वेद के व्यापक संवर्धन के प्रति

राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें गहराई तक समाई हैं और प्रदेश औषधि उत्पादन की अद्वितीय क्षमता रखता है।

सुश्रुत ओपीडी भवन के लोकार्पण के साथ श्री शर्मा ने आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के सशक्त विस्तार का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया, जो राज्य में पारंपरिक चिकित्सा को नई दिशा देने वाला कदम है।

आयुष्मान आदर्श ग्राम - ग्रामीण स्वास्थ्य का नया मॉडल

राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से गांवों में आयुर्वेद और योग आधारित स्वास्थ्य मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का लाभ आम जनता तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। यह पहल गांवों में निवारक स्वास्थ्य सेवा और प्राकृतिक उपचार पद्धति को मजबूत आधार प्रदान कर रही है।

विशेष आयुर्वेद चिकित्सा शिविर

राज्य सरकार की सक्रिय पहल से ग्रामीण अंचलों में आयोजित किए जा रहे आयुर्वेद चिकित्सा शिविरों के माध्यम से आमजन को पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है। इन निःशुल्क शिविरों में रोगियों को आयुर्वेदिक परामर्श, औषधियां तथा उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें दमा, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सायटिका, एसिडिटी, कब्ज, चर्म रोग और स्त्री रोग जैसी समस्याओं का उपचार शामिल है। अर्श, भगन्दर और परिकर्तिका जैसे जटिल रोगों का क्षारसूत्र पद्धति से विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क उपचार एवं शल्य चिकित्सा की जा रही है, वहीं पंचकर्म और अग्निकर्म जैसी प्रक्रियाएं भी संचालित हो रही हैं।

मरीजों को औषधि, भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ करने के लिए स्वर्णप्राशन जैसी विशेष सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

जनस्वास्थ्य, किसान और उद्योग के लिए अवसर

आयुर्वेद आधारित विकास मॉडल किसानों को औषधीय पौधों की खेती में नए अवसर प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण औषधियों के उत्पादन और प्रमाणन से उद्योग को मजबूती मिलती है, जबकि आमजन को सुलभ और सुरक्षित उपचार उपलब्ध होता है। राजस्थान में यह पहल स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का माध्यम भी बन रही है।

राजस्थान बजट में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बल

हाल के राज्य बजट में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। फलौदी, खैरथल-तिजारा, सलूम्बर एवं कोटपूतली-बहरोड़ के आयुर्वेद चिकित्सालयों को जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। तलवाड़ा (गढ़ी)-बांसवाड़ा, चौहटन-बाड़मेर, सुमेरपुर-पाली और छोटी सादड़ी (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़ सहित 30 ब्लॉकों में संचालित औषधालयों को ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाएगा।

समेलिया (दूदू)-जयपुर और सुभाष नगर-कोटा में नए आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित होंगे, जबकि सांगानेर-जयपुर में नवीन आयुष चिकित्सालय तथा शाहपुरा-भीलवाड़ा में 50 बेड क्षमता का एकीकृत आयुष चिकित्सालय बनाया जाएगा। साथ ही अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण आयुर्वेद चिकित्सालयों एवं औषधालयों के भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और रख-रखाव हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह बजट प्रावधान दर्शाता है कि राज्य सरकार आयुर्वेद को जनस्वास्थ्य की मुख्यधारा में लाने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है।

राजस्थान से वैश्विक आयुर्वेद को नई दिशा

राजस्थान की धरती पर आयुर्वेद का यह पुनर्जागरण केवल चिकित्सा प्रणाली का विस्तार नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का सशक्त संगम है। प्रधानमंत्री की वैश्विक दृष्टि और मुख्यमंत्री के सक्रिय प्रयास मिलकर एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं, जहां आयुर्वेद आधुनिक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में स्थापित होगा। जयपुर का उभरता आयुर्वेदिक परिदृश्य भारत को वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने वाला सशक्त अध्याय सिद्ध हो रहा है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024

शैलेन्द्र सिंह, राज.आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा

राजस्थान सरकार ने Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024 को "Enabling Green, Global & Capable Rajasthan" थीम के साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में Ease of Doing Business को सुधारना, लागत कम करना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है।

नीति का उद्देश्य

- राज्य में Ease of Doing Business को बेहतर बनाना एवं व्यवसाय की लागत कम करना।
- घरेलू एवं वैश्विक निवेश आकर्षित करना।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं व्यापक रोजगार सृजन।
- राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करना।
- हरित विकास (Green Growth), निर्यात संवर्धन (Export Promotion) एवं क्षमता विकास (Capability Development) को बढ़ावा देना।

नीति का कार्यक्षेत्र

- नीति 8 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है तथा 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
- केवल राजस्थान में किए गए निवेश एवं उत्पन्न रोजगार को ही प्रोत्साहन हेतु मान्य किया जाएगा।
- FPO/FPC (किसान उत्पादक संगठन/ कंपनी) भी इसके पात्र हैं (न्यूनतम 50 किसान सदस्य)।

तीन स्तरों पर प्रोत्साहन

Tier-1 मानक प्रोत्साहन पैकेज (Standard Incentive Packages) के तहत विनिर्माण, सेवाएं, सनराइज सेक्टर, MSME, स्टार्टअप, औद्योगिक अवसंरचना तथा R&D, GCC एवं टेस्ट लैब्स जैसी इकाइयों को आधारभूत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं।

Tier-2 अतिरिक्त प्रोत्साहन (Add-on Incentives) के अंतर्गत राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए हरित विकास (Green Growth), निर्यात संवर्धन (Export Promotion) तथा क्षमता विकास (Capability Development) से संबंधित अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं।

Tier-3 (अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज) बड़े निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तैयार किए गए विशेष पैकेज हैं, जिनमें निवेश की राशि के आधार पर सिल्वर (500–1000 करोड़ रुपए), गोल्ड (1000–3000 करोड़ रुपए) तथा प्लेटिनम (3000 करोड़ रुपए से अधिक) श्रेणी के प्रोत्साहन शामिल हैं।

विनिर्माण क्षेत्र

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जबकि MSME इकाइयों के लिए यह सीमा 25 करोड़ रुपए रखी गई है। निवेश की राशि और उत्पन्न किए गए रोजगार के आधार पर परियोजनाओं को लार्ज (Large), मेगा (Mega) और अल्ट्रा-मेगा (Ultra-Mega) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अनुसार उन्हें विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन (Asset Creation Incentives)

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उद्योगों को परिसंपत्ति सृजन हेतु तीन प्रकार के प्रोत्साहनों में से किसी एक विकल्प का चयन करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रथम, निवेश सब्सिडी (Investment Subsidy) के अंतर्गत उद्योगों को 7 वर्षों तक 75 प्रतिशत राज्य कर की प्रतिपूर्ति दी जाती है। द्वितीय, पूंजी सब्सिडी (Capital Subsidy) के तहत पात्र स्थायी पूंजी निवेश (EFCI) पर क्षेत्र एवं निवेश के आधार पर 13 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसका भुगतान 10 वर्षों तक वार्षिक किस्तों में किया जाता है। तृतीय, टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन (Turnover Linked Incentive – TLI) के अंतर्गत उद्योगों को 10 वर्षों तक नेट सेल्स टर्नओवर का 1.2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य उद्योगों को उनकी निवेश आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त प्रोत्साहन विकल्प प्रदान करना है।

अतिरिक्त बूस्टर

- **रोजगार प्रोत्साहन बूस्टर** – निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक रोजगार सृजन करने पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन।
- **प्राथमिकता क्षेत्र प्रोत्साहन बूस्टर** – राज्य द्वारा चिन्हित थ्रस्ट

(प्राथमिक) क्षेत्रों में निवेश करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ।

- **एंकर इकाई प्रोत्साहन बूस्टर** – किसी क्षेत्र या क्षेत्रीय क्लस्टर में प्रथम प्रमुख (Mega/Ultra-Mega) इकाइयों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- **ब्याज अनुदान (Interest Subvention – 5 वर्ष)**- संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश हेतु लिए गए टर्म लोन पर 5 वर्ष तक 5 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष रियायतें

इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को विभिन्न विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं। इनमें 7 वर्षों तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट, 100 प्रतिशत मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट शामिल है। इसके अतिरिक्त, RIICO से ली जाने वाली भूमि के लिए 10 वर्षों का लचीला भुगतान मॉडल उपलब्ध कराया गया है, जिससे उद्योगों पर प्रारंभिक वित्तीय बोझ कम हो और निवेश को प्रोत्साहन मिले।

सेवा क्षेत्र

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जबकि पर्यटन क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 करोड़ रुपए रखी गई है। पात्र इकाइयों को 10 से 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 1 से 1.4 प्रतिशत तक टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन (TLI) तथा 75 प्रतिशत तक राज्य कर की प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। सेवा क्षेत्र की कंपनियों को कार्यालय स्थान के लीज रेंटल पर 5 वर्षों तक 25 प्रतिशत सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रारंभिक संचालन लागत में कमी आए और निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।

उभरते क्षेत्र

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर, बैटरी टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक तथा वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे उच्च तकनीक एवं भविष्य उन्मुख क्षेत्रों को Sunrise Sectors के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु आधार प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक का Sunrise Booster प्रदान किया जाता है, जिससे राज्य में उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का विकास और वैश्विक निवेश आकर्षण सुनिश्चित हो सके।

MSME एवं स्टार्टअप

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत MSME और स्टार्टअप इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। MSME इकाइयों को 75 प्रतिशत तक SGST प्रतिपूर्ति, 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान तथा एग्री-प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए पूंजी सब्सिडी का लाभ दिया जाता है, जिससे छोटे एवं मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके। वहीं स्टार्टअप्स के लिए Sunrise सेक्टर में Seed Support, व्यवसाय इन्क्यूबेशन सहायता तथा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 2 वर्ष तक 100 प्रतिशत SGST प्रतिपूर्ति जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल सके।

हरित विकास

इस योजना के अंतर्गत हरित विकास (Green Growth) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, Captive Power Plant में किए गए निवेश को EFCI (Eligible Fixed Capital Investment) में शामिल करने की अनुमति दी गई है, जिससे उद्योगों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त बिजली के ट्रांसमिशन शुल्क में छूट प्रदान कर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, ताकि राज्य में सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 राजस्थान को निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक व्यापक, संरचित एवं प्रतिस्पर्धी नीति ढांचा प्रदान करती है। यह नीति राज्य को हरित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने, निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, MSME क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिससे संतुलित और सतत आर्थिक विकास को गति मिल सके। यह नीति राजस्थान को केवल एक औद्योगिक राज्य नहीं, बल्कि नवाचार, हरित ऊर्जा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। राजस्थान सरकार का संकल्प स्पष्ट है — निवेश बढ़े, उद्योग फले-फूले, रोजगार सृजित हों और प्रदेश सतत विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।

77वां गणतंत्र दिवस

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने लोकभवन एवं एस.एम.एस. स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास, शासन सचिवालय और बड़ी चौपड़ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी एवं विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

अब विद्यालयों में दैनिक कार्यारम्भ वंदे मातरम् से

वंदे मातरम् के गायन-वादन की आधिकारिक प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी

श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सम्बन्ध में हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में राष्ट्र गीत के आधिकारिक रूप, इसे किन अवसरों पर गाया या बजाया जाना चाहिए और उन अवसरों पर उसका सम्मान बनाए रखने के लिए किस प्रकार का शिष्टाचार अपनाया जाना आवश्यक है, सभी बातें स्पष्ट की गई हैं। राष्ट्र गीत को गाने अथवा बजाने का समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है।

राष्ट्र गीत का वादन

राष्ट्र गीत का आधिकारिक संस्करण सिविल सम्मान समारोहों के अवसर पर, औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से पहले और बाद में, राज्यपाल/उपराज्यपाल के अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में औपचारिक राजकीय समारोहों में आने पर और ऐसे समारोहों से उनके जाते समय और जब राष्ट्रीय झंडे को परेड में लाया जाए, तब बजाया जाएगा। साथ ही किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्र गीत बजाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों। जब बैंड के साथ राष्ट्र गीत गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्र गीत प्रारम्भ होने वाला है, राष्ट्र गीत शुरू होने से पहले मृदंग बजाए जाएंगे।

राष्ट्र गीत का सामूहिक गायन

परेडों को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर, औपचारिक राज्य समारोहों को छोड़कर किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले इसे सामूहिक रूप से गाया जाएगा, उन सभी अवसरों पर जब राष्ट्र गीत को गाया जाता है, इसे सामूहिक रूप से गाने के साथ इसके आधिकारिक संस्करण का पाठ गाया जाएगा। उन अवसरों पर भी राष्ट्र गीत गाया जा सकता है, जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्त्वपूर्ण हैं। सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्र गीत के सहगान से प्रारंभ होना चाहिए। विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को लोकप्रिय बनाने तथा राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

राष्ट्र गान से पहले राष्ट्र गीत गाया या बजाया जाएगा

जब कभी राष्ट्र गीत का गायन अथवा वादन हो तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार दर्शन अथवा वृत चित्र के दौरान राष्ट्र गीत फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती, क्योंकि खड़े होने से राष्ट्र गीत के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन में बाधा पड़ती है और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न होती है। जब राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान दोनों गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्र गीत पहले गाया या बजाया जाएगा।

राष्ट्र गीत के प्रमुख तथ्य

वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (चटर्जी) ने की थी। यह पहली बार वर्ष 1875 में बंगदर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। बाद में उनके उपन्यास आनंदमठ में सम्मिलित किया गया। जिसे संगीतबद्ध रवींद्र नाथ टैगोर ने किया। यह भारत की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहचान के रूप में भी लिया जाता है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिए जाने की घोषणा 24 जनवरी, 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में चुना गया।

सम्पूर्ण राष्ट्रगीत अंतिम पृष्ठ पर...

राजस्थान की तीन हस्तियों
को पद्म श्री पुरस्कार

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं, जो तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहो में प्रदान किए जाते हैं, जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल में होते हैं। वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने 131 पद्म (5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री) पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिनमें 2 युगल पुरस्कार (युगल पुरस्कार को एक ही माना जाता है) शामिल हैं।

इस बार अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दो लोगों को कला और एक को समाज सेवा में योगदान के लिए पद्म श्री सम्मान मिलेगा। इन लोगों ने जीवन भर अपनी साधना से विलुप्त होती लोक विधाओं को जीवित रखने और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया। जिन लोगों को पद्मश्री सम्मान मिलेगा, उनमें गफरुद्दीन मेवाती (जोगी- कला), स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज (समाज सेवा) और तगाराम भील (कला) का नाम शामिल है।

गफरुद्दीन मेवाती जोगी (कला)

डीग जिले के गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान की लोक कला को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। वे 'पांडुन का कड़ा' जैसे पारंपरिक लोक गीतों के संरक्षक हैं और 2,500+ दोहों की स्मृति से प्रस्तुति देते हैं।

भपंग- भपंग डमरू के आकार का वाद्य होता है। इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है, जिसे कांख में दबाकर और डोर को खींचते हुए वादन किया जाता है। वादक लकड़ी के टुकड़े से इसे बजाकर अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करता है।

पांडुन का कड़ा- सदियों से महाभारत के कई रोचक रूपांतरण देखने को मिलते रहे हैं। पांडवों का दोहा (पांडुन का कड़ा) ऐसा ही एक रूपांतरण है। इसमें कलाकार पहले दोहा का पाठ करते हैं और फिर धानी राग में गाते हुए उसका विस्तार से वर्णन करते हैं।

तगाराम भील (कला)

जैसलमेर के तगा राम भील अलगोजा वादक और आदिवासी संगीत परंपरा के सशक्त प्रतिनिधि हैं। उन्होंने तीन दशकों से अधिक समय से राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को देश–विदेश में प्रसारित किया है। वर्ष 1981 में जैसलमेर के मरू महोत्सव से उनका मंचीय सफर शुरु हुआ, जो 1996 में फ्रांस तक पहुंचा।

अलगोजा – अलगोजा समान आकार की दो चोंचवाली बांस की बांसुरियों की जोड़ी होता है। इस पर पांच अंगुलियों के लिए छिद्र और प्रत्येक बांसुरी पर एक संकीर्ण मुखनाल होता है। दोनों बांसुरी, वादक द्वारा एक साथ फूंकी जाती हैं। इसे अलवर, राजस्थान, के 'मेव' समुदाय द्वारा उनके लोक और जनजातीय गीतों के साथ संगत वाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है।

स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज (समाज सेवा)

स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए अद्भुत कार्य किया है।

स्वामी ब्रह्मदेव महाराज श्रीगंगानगर में श्री जगदंबा अंधविद्यालय के संस्थापक हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदंबा अंधविद्यालय की स्थापना की थी, जो दृष्टि बाधित (अंध) बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस संस्थान में मूक-बधिर विद्यालय भी संचालित किया जाता है।

देश का पहला ब्रेल लिपि एटीएम - वर्ष 2007 में श्री जगदंबा अंध विद्यालय में देश का पहला ब्रेल लिपि युक्त एटीएम स्थापित किया गया, जो दृष्टिबाधितों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई।

राजस्थान डिस्कॉम्स को पीएम कुसुम योजना में गोल्ड अवार्ड

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से राजस्थान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट-सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया। राजस्थान डिस्कॉम्स चेयरपर्सन सुश्री आरती डोगरा ने यह अवार्ड मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया। श्री शर्मा ने इस उपलब्धि पर डिस्कॉम्स के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी।

साइबर सुरक्षा सामूहिक संकल्प, विशेष साइबर कोर्ट होगा स्थापित

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'साइबर सुरक्षा- जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री सूर्यकांत ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल क्रांति ने अपार सुविधाएं प्रदान की हैं तथा इससे शासन, सेवाएं और संवाद पहले से कहीं अधिक सुलभ हुए हैं। परंतु इसके दुरुपयोग होने से चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में साइबर सुरक्षा केवल बैंक खातों की सुरक्षा नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वास की रक्षा का भी विषय बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर सुरक्षा सामूहिक संकल्प है तथा इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार, न्यायपालिका और समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने साइबर अपराध पर कठोर नियंत्रण के लिए प्रदेश में विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना की घोषणा की। इस अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्म ई-समाधान की लॉन्चिंग, मध्यस्थता पर हैंडबुक का विमोचन एवं "महिला पंचायत पैन राजस्थान" का शुभारंभ किया गया।

निवर्तमान सरपंच (प्रशासक) प्रदेश अधिवेशन

सरपंच गांवों के विकास की धुरी- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

जयपुर में सरपंच संघ द्वारा आयोजित निवर्तमान सरपंच (प्रशासक) प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांवों की लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक हैं। वे विकास की धुरी हैं, जिनके समर्पण भाव से किए गए कार्यों से ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली आती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूल मंत्र को ग्रामीण परिवेश में सरपंच धरातल पर उतारते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया वीबी जी राम जी कानून ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, केन्द्रीय बजट में योजना के लिए 95 हजार 692 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से मनरेगा की अनियमितताओं को दूर किया गया है। इसके अंतर्गत स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी। कानून में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। साथ ही राज्य सरकार भी पंचायतीराज को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में 8 नई जिला परिषदों, 94 नई पंचायत समितियां एवं 3 हजार 467 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है।

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. - 06

1. **भारत का पहला वैश्विक स्तर पर आधारित सूचकांक 'रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स' किसने जारी किया।**
   a. श्री नरेंद्र मोदी b. श्री रामनाथ कोविंद
   c. श्री अमित शाह d. श्री राजनाथ सिंह

2. **हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए श्री पीयूष पांडे (मरणोपरांत) को निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया है।**
   a. कला b. खेल
   c. सामाजिक कार्य d. साहित्य और शिक्षा

3. **77 वें गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी 'गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट' 'रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श' को पॉपुलर चॉइस श्रेणी में कौन सा स्थान मिला।**
   a. पहला b. दूसरा c. तीसरा d. चौथा

4. **भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDS) द्वारा संचालित भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी "पैलेस ऑन व्हील्स" की शुरुआत किस वर्ष हुई थी।**
   a. 1982 b. 1980 c. 1999 d. 1988

5. **देश में 10 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण देने के लिए 'AI स्किलिंग कार्यक्रम' की शुरुआत कहां से की गई?**
   a. जोधपुर b. जयपुर
   c. दिल्ली d. मुम्बई

6. **ग्लोबल साइबर पीस समिट 2.0 में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड" से नवाजा गया है।**
   a. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय b. राजस्थान विश्वविद्यालय
   c. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर d. आई.आई.टी., जोधपुर

7. **उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है?**
   a. प्रतापगढ़ b. सलूंबर
   c. डूंगरपुर d. चित्तौड़गढ़

8. **भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान देश में कितने प्रतिशत उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर है?**
   a. 50.37 प्रतिशत b. 47.85 प्रतिशत
   c. 40.12 प्रतिशत d. 27.17 प्रतिशत

9. **भ्रमर माता का मंदिर कहां स्थित है?**
   a. छोटी सादड़ी b. आभानेरी
   c. सलूंबर d. जगत

10. **प्रसार भारती ने देशभर के डिजिटल रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर किस पहल की शुरुआत की है?**
    a. क्रिएटर्स कॉर्नर b. डिजिटल प्रतिभा मंच
    c. क्रिएटिव हब d. इनोवेशन कॉर्नर

11. **किस वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान का 19 वां ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया गया है?**
    a. रणथंभौर अभयारण b. कुंभलगढ़ अभयारण
    c. केवलादेव अभयारण d. तालछापर अभयारण

12. **भीलवाड़ा की 17 वर्षीय जिजीविषा जोशी ने किस क्षेत्र में देश रत्न पुरस्कार व इंडियन ग्लोरी पुरस्कार जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।**
    a. लेखन b. कला c. अभिनय d. खेल

13. **हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को GI Tag दिया गया?**
    a. नागौरी अश्वगंधा b. सोजत मेहन्दी
    c. सरवती गेंहू d. ईसबगोल

14. **देश का पहला अमरूद महोत्सव कहां मनाया गया?**
    a. डूंगरपुर b. बांसवाड़ा
    c. प्रतापगढ़ d. सवाई माधोपुर

15. **जर्मनी में जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी 'BIOFACH 2026' में भारत को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।**
    a. कंट्री ऑफ द ईयर b. लीडरशिप अवॉर्ड ऑफ द ईयर
    c. कंट्री ऑफ द सेंचुरी d. ग्लोबल लीडर ऑफ 2026

16. **विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है?**
    a. खेजड़ली गांव, जोधपुर b. मावली गांव, उदयपुर
    c. राजगढ़ गांव, अलवर d. सम गांव, जैसलमेर

17. **मरु महोत्सव 2026 की थीम क्या रखी गई?**
    a. Desert Heritage festival b. Colors of Rajasthan
    c. Beats of the Thar d. Golden Sands Celebration

18. **राज्य सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया?**
    a. वूमेन ऑफ जिंक अभियान b. सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान
    c. प्रेरणा अभियान 2.0 d. समग्र शिक्षा अभियान

19. **भारत सरकार की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान देश में 14.82 प्रतिशत के योगदान के साथ कौनसे स्थान पर है?**
    a. प्रथम b. द्वितीय c. तृतीय d. चतुर्थ

प्रश्नोत्तरी नं. 05 के उत्तर एवं विजेताओं के नाम

प्रश्नोत्तरी नं. – 05 (उत्तर) 1 (b), 2(b), 3(d), 4 (b), 5(a), 6(c), 7(d), 8(d), 9 (a),10(c),11(a),12(c),13 (a),14(c),15(b),16 (b),17(b),18(a),19(c)

मोहसिन खान कायमखानी
मेंघरास, भीलवाड़ा

महेन्द्र साहू
राजसमंद

कमल वर्मा
जयपुर

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 मार्च, 2026 तक ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें। प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के फोटो सहित नाम एवं सही उत्तर 'राजस्थान सुजस' के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगे व प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को डीआईपीआर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

सरकार @ 2 वर्ष

प्रगति एवं उत्कर्ष

2024–25–2026

वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के कार्य एवं उपलब्धियां

राज्य सरकार का विज़न है कि राजस्थान को आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध प्रदेश के रूप में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया जाए। साथ ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक धरोहर को और अधिक सुदृढ़ कर सर्वांगीण विकसित राज्य के एक मॉडल के रूप में राज्य देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए।

गत दो वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय कर राज्य में संवेदनशील, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को प्रेरणा मानते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी शक्ति को आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ़ करना सरकार का मूल मंत्र है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय की परिकल्पना 'भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने' को साकार करने में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'भारत @ 2047' की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप **'विकसित राजस्थान @ 2047'** विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।

आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास तथा समावेशी प्रगति को केन्द्र में रखते हुए तैयार किया गया यह दस्तावेज राज्य को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है।

'विकसित राजस्थान @ 2047' विज़न में उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और पर्यावरण स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ उर्जा परियोजनाओं का विस्तार करना, डिजिटल शासन को बढ़ाना और समावेशी सामाजिक विकास सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार जल संरक्षण, हरित अवसंरचना और राजस्थान की महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए लक्षित प्रयासों, नवाचारों एवं केंद्रीय योजनाओं में राज्य को प्राप्त सहयोग से राज्य राष्ट्रीय स्तर पर 12 योजनाओं में प्रथम स्थान, 4 योजनाओं में द्वितीय स्थान तथा 7 योजनाओं में तृतीय स्थान प्राप्त कर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में रहा है। राज्य को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2, 3 और बजट घोषणाओं एवं संकल्प पत्र के बिन्दुओं की क्रियान्विति परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राजस्थान

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2025) - 2.18 करोड़ पॉलिसियां : देश में प्रथम
- पीएम कृषि सिंचाई योजना - 'Per Drop - More Crop' - 1.31 लाख हेक्टेयर माइक्रो इरिगेशन स्थापना : देश में द्वितीय
- कृषि विभाग : प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस रजत पुरस्कार
- पीएम-कुसुम (कम्पोनेंट-B एवं C-FLS) : देश में तृतीय
- पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-A) (अक्षय एवं सौर ऊर्जा स्थापना) : देश में प्रथम
- पीएम-कुसुम योजना (कम्पोनेंट-C) : सौर ऊर्जा स्थापना में देश में प्रथम
- फार्मर रजिस्ट्री योजना : लाभार्थी ID निर्माण प्रतिशत में राष्ट्रीय प्रथम
- आयुष्मान भारत (PM-JAY) : क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट, देश में तृतीय
- नेशनल प्रोग्राम फॉर पेलिएटिव केयर : उत्कृष्ट योगदान, देश में तृतीय
- अंगदान एवं प्रत्यारोपण : वर्ष 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार व प्रथम स्थान
- टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान 2024 : देश में तृतीय
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 : 62,915 स्थलों पर 85 लाख से अधिक प्रतिभागी, देश में प्रथम
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रैंकिंग : पोषण पखवाड़ा 2025 गतिविधियों में देश में प्रथम
- पोषण माह 2025 गतिविधियों में, देश में द्वितीय
- तंबाकू-फ्री यूथ कैंपेन 2.0 : बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, देश में तृतीय
- पीएम विश्वकर्मा योजना : ऋण स्वीकृति एवं वितरण, देश में द्वितीय
- One District One Product Programme (ODOP) : क्रियान्वयन श्रेणी में ब्रॉन्ज अवॉर्ड
- जल संचय जनभागीदारी 1.0 अभियान (पंचायती राज) : कार्य क्रियान्वयन के आधार पर, देश में तृतीय
- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) - स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 : लक्षित इकाइयों के रूपांतरण में प्रथम
- फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 : देश के 10,443 कार्यक्रमों में से 6202 केवल राजस्थान में, देश में प्रथम
- विकसित भारत संकल्प यात्रा : 11,209 कैंप, 5.94 लाख उज्ज्वला कनेक्शन - देश में प्रथम
- खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार
- जनजाति कल्याण एवं सशक्तीकरण : धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट

वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की वर्ष 2024 से पूर्व के पाँच वर्ष की उपलब्धियों से तुलना

परिशिष्ट–2

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
1.	जल के कुशलतम उपयोग हेतु पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक	संख्या	98753	46183	91582
2.	कृषि में 10+2, स्नातक स्नातकोत्तर एवं पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को वितरित प्रोत्साहन राशि	करोड़ रुपए	129.26	21.52	70.00
3.	तारबंदी पर कृषकों को दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	377.66	8.20	113.00
4.	फार्म पौण्ड (खेत तलाई)	संख्या	35368	8152	29430
5.	फार्म पौण्ड (खेत तलाई) पर कृषकों को अनुदान	करोड़ रुपए	303	43	202
6.	खेतों पर तारबंदी	लाख मीटर	344	8	113
7.	पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन	संख्या	101	1	36
8.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन	संख्या	50	0	13
9.	राष्ट्रीय आयुष मिशन में प्राप्त केन्द्रीय सहायता	करोड़ रुपए	150.52	23.00	113.00
10.	राजकीय चिकित्सालय का जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नयन	संख्या	6	0	0
11.	लैम्प्स का गठन	संख्या	296	22	201
12.	मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अतंर्गत किसानों को देय राशि	रुपए	3000	0	0
13.	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत लाभार्थी	संख्या	79698	12689	54858
14.	सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरें	संख्या	13619	500	2813
15.	शैक्षणिक संस्थानों में लगाए गये सीसीटीवी कैमरे	संख्या	1645	0	1000
16.	सौर ऊर्जा से उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि	मेगावाट	19000	2000	15000
17.	बायो गैस से उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि	मेगावाट	79.07	0.00	8.00
18.	कुसुम घटक A के अन्तर्गत जारी किए गए एलओए	संख्या	2911	0	489
19.	कुसुम घटक C के अन्तर्गत जारी किए गए एलओए	संख्या	2064	0	57
20.	बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि	मेगावाट	7395	1497	3952
21.	400 केवी सबस्टेशन स्थापित	संख्या	2	1	1

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
22.	132 केवी सबस्टेशन स्थापित	संख्या	45	20	38
23.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु आवंटित भूमि	हैक्टेयर	98894	2973	22597
24.	कुसुम A के तहत एलओए	मेगावाट	5276	0	595
25.	कुसुम C के तहत एलओए	मेगावाट	5202	0	114
26.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना से लाभान्वित छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वितरित राशि	करोड़ रुपए	18.56	0.00	8.75
27.	मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना से लाभान्वित छात्राएं	संख्या	693	0	570
28.	मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना से लाभान्वित छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वितरित राशि	करोड़ रुपए	4.78	0.00	3.52
29.	छात्राओं को स्कूटी वितरित	संख्या	39860	13719	21136
30.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना से लाभान्वित छात्राएं	संख्या	36140	0	16563
31.	राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण	संख्या	185	9	57
32.	पेपरलीक प्रकरणों में गिरफ्तारियां	संख्या	420	7	299
33.	ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना	हैक्टेयर	203133	29609	183428
34.	ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों पर दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	888.24	148.68	842.11
35.	फव्वारा संयंत्रों पर दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	244.09	56.71	237.83
36.	शेडनेट हाउस पर दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	37.38	2.78	15.78
37.	शेडनेट हाउस की स्थापना	वर्ग मीटर	968000	99000	860000
38.	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी लाभार्थी	संख्या	113499	2967	39428
39.	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के अन्तर्गत दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	1133.30	69.25	589.71
40.	प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के अंतर्गत स्वीकृत आवास	संख्या	79027	4636	77950
41.	उप जिला चिकित्सालय पर आवासीय भवन निर्माण	संख्या	3	0	0
42.	50 बेड वाले मातृ-शिशु केन्द्र के भवन निर्माण	संख्या	2	0	0
43.	मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैशलैस सुविधा हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि	करोड़ रुपए	7645	1900	7357
44.	कॉकलियर इंप्लांट लाभार्थी	संख्या	533	0	366

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
45.	कॉकलियर इंप्लांट पर कैशलैस सुविधा हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि	करोड़ रुपए	20.13	0.00	15.18
46.	किडनी ट्रांसप्लांट लाभार्थी	संख्या	958	58	708
47.	किडनी ट्रांसप्लांट पर कैशलैस सुविधा हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि	करोड़ रुपए	41.33	1.02	30.44
48.	लिवर ट्रांसप्लांट लाभार्थी	संख्या	91	0	60
49.	बोनमैरो ट्रांसप्लांट लाभार्थी	संख्या	361	0	88
50.	बोनमैरो ट्रांसप्लांट पर कैशलैस सुविधा हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि	करोड़ रुपए	19.34	0.00	5.73
51.	जिला अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करवाये गये वेंटिलेटर (बेसिक एवं एडवांस)	संख्या	255	63	74
52.	सैटेलाईट अस्पताल की स्थापना	संख्या	18	0	10
53.	उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण	संख्या	984	277	515
54.	प्रधान खनिज ब्लॉक्स की नीलामी	संख्या	76	1	34
55.	अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अल्पसंख्यक अभ्यर्थी	संख्या	4736	73	3370
56.	अल्पसंख्यकों के लिए अनुप्रति योजना/ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	17.57	0.20	3.88
57.	अल्प संख्यक विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावासों का निर्माण	संख्या	30	7	19
58.	स्वामित्व कार्ड वितरित	संख्या	1390000	0	175000
59.	ओडीएफ प्लस मॉडल गांव	संख्या	41037	0	1478
60.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान/जल संचय योजना के अन्तर्गत व्यय राशि	करोड़ रुपए	1777.47	49.70	1233.11
61.	पूर्ण की गई वृहद पेयजल परियोजनाएं (Packages)	संख्या	30	0	13
62.	नवीन सड़कों के निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	7541.60	1657.42	6910.50
63.	मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	4178.86	935.00	3174.72
64.	निर्मित नवीन सड़कों की लम्बाई	किलोमीटर	16430	4248	13160
65.	सड़कों से जोड़े गए गांव	संख्या	1698	164	1104

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
66.	मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण	किलोमीटर	9104	2035	6614
67.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु आवंटित भूमि	हैक्टेयर	98894	2973	22597
68.	नवीन राजस्व ग्रामों का सृजन	संख्या	2294	15	1517
69.	राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण	करोड़ रुपए	5492	1202	4382
70.	स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई आजीविका संवर्धन राशि	करोड़ रुपए	544.58	109.48	521.10
71.	संस्कृत महाविद्यालयों का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन	संख्या	17	1	3
72.	प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों का वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में क्रमोन्नयन	संख्या	224	50	103
73.	विद्यालय भवन निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	107.45	57.41	98.37
74.	टेबलेट वितरण पर व्यय	करोड़ रुपए	163.54	0	0
75.	स्कूली विद्यार्थियों को टेबलेट/लेपटॉप वितरण	संख्या	88724	0	0
76.	स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण	संख्या	1051000	350000	1036000
77.	कौशल प्रशिक्षण	संख्या	341347	104667	235000
78.	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित महिलाएं	संख्या	119146	51325	117863
79.	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित दिव्यांग	संख्या	16062	2822	8695
80.	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पेंशनर	संख्या	5198551	4757856	5125264
81.	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पेंशनर	संख्या	1934730	1620032	1839098
82.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पेंशनर	संख्या	832450	768669	805368
83.	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित पेंशनर	संख्या	417114	371713	385916
84.	पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित	संख्या	615098	471999	586318
85.	अनुसूचित जाति अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी	संख्या	11195	531	10787

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
86.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुप्रति योजना /मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी	संख्या	3677	0	3609
87.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में समस्त पेंशनर्स को देय न्यूनतम पेंशन राशि	रुपए	1250	750	1000
88.	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना	संख्या	21	1	5
89.	देशी पर्यटकों का आगमन	करोड़	48.25	6.73	37.67
90.	कुल पर्यटकों का आगमन	करोड़	48.65	6.94	38.09
91.	नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा	हैक्टेयर	99562	17448	52182

वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों की वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धियों से तुलना

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
1.	डिग्गी निर्माण	संख्या	7959	4832	13902
2.	महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनिकिट वितरण	संख्या	6150000	2021000	8500000
3.	जल के कुशलतम उपयोग हेतु पाइपलाइन पर उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	85.39	43.81	150
4.	चारा मिनिकिट वितरण	संख्या	214000	103000	490000
5.	फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषक (फसल पॉलिसी)	संख्या	90200000	18400000	141600000
6.	फसल बीमा योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई गई मुआवजा राशि (बीमा क्लेम)	करोड़ रुपए	6415	6323	22533
7.	कृषि में 10+2, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण	संख्या	71502	29404	95013
8.	नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना	संख्या	2	0	0
9.	पशु चिकित्सा उप केन्द्र का पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन	संख्या	151	0	325
10.	नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना	संख्या	700	600	2422
11.	गौशालाओं को प्रदत्त सहायता राशि	करोड़ रुपए	2501	934	3117
12.	निर्माणाधीन आयुष औषधालय/ चिकित्सालयों पर व्यय	करोड़ रुपए	42.00	21.00	44.49
13.	आयुर्वेद महाविद्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर विषय	संख्या	3	0	6
14.	औषधि क्रय	करोड़ रुपए	92.69	48.92	112.28
15.	नये पैक्स का गठन	संख्या	1563	196	1921
16.	केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा मध्यकालीन ऋण वितरण	करोड़ रुपए	1355	577	1566
17.	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरित किसानो की संख्या	संख्या	10624	8261	25731
18.	राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण	करोड़ रुपए	383.55	224.04	716.83
19.	नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन	संख्या	1859	218	2122

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
20.	कस्टम हाईरिंग केन्द्रों की स्थापना	संख्या	412	152	1030
21.	ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण	संख्या	505	387	1117
22.	केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण	करोड़ रुपए	48325	22224	79664
23.	कुल दी गई नियुक्तियां	संख्या	98650	90638	207570
24.	ई-मित्र के माध्यम से नई सेवाएं प्रारम्भ	संख्या	273	242	830
25.	किसानों को बिजली बिलों में अनुदान	करोड़ रुपए	48591	28180	81735
26.	220 केवी के नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित	संख्या	5	2	5
27.	कृषि कनेक्शन	संख्या	204819	170601	453331
28.	शहरी क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन	संख्या	321105	238975	662468
29.	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण	हेक्टेयर	148725	37620	213401
30.	राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	730	105	875
31.	नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों की स्थापना	संख्या	25	13	128
32.	राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर क्रमोन्नत	संख्या	17	12	81
33.	राजकीय महाविद्यालय स्नातकोत्तर पर नवीन विषय	संख्या	50	19	213
34.	राजकीय महाविद्यालयों में नवीन विषय (स्नातक)	संख्या	73	17	135
35.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	152955	133857	359755
36.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वितरित राशि	करोड़ रुपए	73.59	58.66	161.36
37.	नवीन पुलिस थानों का सृजन	संख्या	23	2	77
38.	नवीन पुलिस चौकी सृजित	संख्या	35	0	133
39.	सोलर पम्प सेट की स्थापना	संख्या	59039	13466	63140
40.	फव्वारा संयत्रों की स्थापना	हैक्टेयर	237000	71701	339000
41.	सोलर पम्प सेट पर दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	921.63	128.11	1152.52
42.	ग्रीन हाउस की स्थापना	वर्ग मीटर	3635316	829019	5018847
43.	ग्रीन हाउस पर दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	164.43	65.76	212.69
44.	प्याज भण्डारण गृहों का निर्माण	संख्या	3229	1574	10699

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
45.	रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	31	16	69
46.	रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्ड	संख्या	2453	1585	6457
47.	औद्योगिक क्षेत्रों पर कुल खर्चा	करोड़ रुपए	2007	705	2445
48.	सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की स्थापना	संख्या	1161312	213757	1293886
49.	सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) की स्थापना से पूंजी विनियोजन	करोड़ रुपए	26860	26315	32532
50.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित निर्माण श्रमिक	संख्या	784685	348803	805204
51.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को प्रदान की गई सहायता राशि	करोड़ रुपए	870	551	1310
52.	नगरपालिका से नगर परिषद में क्रमोन्नत	संख्या	4	0	10
53.	नवीन नगरपालिका का गठन	संख्या	52	3	86
54.	स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थी	संख्या	3753000	1171000	5100000
55.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन	संख्या	132	110	610
56.	नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	संख्या	16	0	76
57.	उप जिला अस्पताल की स्थापना	संख्या	61	1	74
58.	जिला अस्पताल की स्थापना	संख्या	14	1	27
59.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण	संख्या	292	150	397
60.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण	संख्या	86	52	129
61.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय भवन निर्माण	संख्या	9	2	31
62.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवासीय भवन निर्माण	संख्या	11	0	15
63.	शैय्याओं की संख्या में वृद्धि	संख्या	2519	1270	18134
64.	लिवर ट्रांसप्लांट पर कैशलैस सुविधा हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि	करोड़ रुपए	3.88	0.00	4.20
65.	जिला अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई गई सोनोग्राफी मशीन	संख्या	89	30	108
66.	नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना	संख्या	7	2	11
67.	घरेलू पाइपलाइन कुकिंग कनेक्शन	संख्या	200278	11483	265000
68.	जल संग्रहण संरचनाओं हेतु जारी स्वीकृतियां	संख्या	132139	38260	137927

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
69.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान/जल संचय योजना के अन्तर्गत पूर्ण कार्य	संख्या	110273	18043	135660
70.	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि	करोड़ रुपए	8816	1862	14966
71.	राज्य वित्त आयोग अंतर्गत व्यय राशि	करोड़ रुपए	6633	2822	13694
72.	राज्य वित्त आयोग अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्य	संख्या	287435	118428	361634
73.	केन्द्रीय वित्त आयोग अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्य	संख्या	226210	185590	432158
74.	आवास विहीन गरीब परिवारों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन	संख्या	16082	5156	28467
75.	बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन	संख्या	8520	5943	38582
76.	पुराने आवासीय भवनों के पटटे जारी	संख्या	184524	154551	1298293
77.	पेयजल से लाभान्वित FHTC (घरेलू नल कनेक्शन)	संख्या	1429000	104609	3661000
78.	पेयजल परियोजनाओं पर समग्र व्यय (CSS+SF)	करोड़ रुपए	16582	1364	30883
79.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	1669	1015	3854
80.	आरओबी पूर्ण	संख्या	10	0	14
81.	आरयूबी पूर्ण	संख्या	14	0	39
82.	सड़कों का निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण	किलोमीटर	41943	25063	69963
83.	सड़कों के निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	27860	10788	36637
84.	निस्तारित किए गए राजस्व प्रकरण	संख्या	448840	138499	555916
85.	राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई सहायता राशि	करोड़ रुपए	673.82	195.60	769.93
86.	महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यय राशि	करोड़ रुपए	17077.38	16278.48	45717.34
87.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पूर्ण कार्य	संख्या	6915	6218	11915
88.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	311.73	262.47	556.13
89.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पूर्ण कार्य	संख्या	41929	21499	55233
90.	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	1958.66	748.21	2256.10
91.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जारी नवीन स्वीकृतियां	संख्या	718392	705801	1031128

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
92.	स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिनको आजीविका संवर्धन राशि उपलब्ध कराई गई	संख्या	64176	26727	91092
93.	स्वयं सहायता समूहों की संख्या जिनको रिवाल्विंग फण्ड राशि उपलब्ध कराई गई	संख्या	74267	57425	165154
94.	स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई रिवाल्विंग फण्ड राशि	करोड़ रुपए	129.24	86.12	248.83
95.	नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना	संख्या	90	32	432
96.	विद्यालय भवन निर्माण	संख्या	131	74	231
97.	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	संख्या	3627	3512	25211
98.	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण पर व्यय	करोड़ रुपए	428.13	341.45	2012.10
99.	इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से लाभान्वित बालिकाएं	संख्या	2528	1208	5144
100.	इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में उपलब्ध करवाई गई प्रोत्साहन राशि	करोड़ रुपए	20.67	9.92	44.82
101.	बालिका प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित बालिकाएं	संख्या	182002	111383	292507
102.	बालिका प्रोत्साहन योजना में उपलब्ध करवाई गई प्रोत्साहन राशि	करोड़ रुपए	91.00	55.69	146.25
103.	गार्गी पुरस्कार योजना से लाभान्वित बालिकाएं	संख्या	205574	156713	380708
104.	गार्गी पुरस्कार योजना अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई प्रोत्साहन राशि	करोड़ रुपए	61.67	47.01	114.21
105.	कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों में आशार्थियों का प्रारम्भिक चयन	संख्या	119740	41406	135090
106.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	402	332	734
107.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	0.12	0.10	0.28
108.	सुखद दाम्पत्य जीवन योजनान्तर्गत लाभान्वित दिव्यांग	संख्या	447	396	1245
109.	सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	6.16	4.07	7.51
110.	सिलिकोसिस योजनान्तर्गत लाभान्वित पीड़ित एवं परिवार	संख्या	5830	4615	34675
111.	सिलिकोसिस योजनान्तर्गत प्रदान की गई सहायता राशि	करोड़ रुपए	176.51	95.00	911.02
112.	सहयोग एवं उपहार योजना/ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत लाभान्वित	संख्या	25389	13434	58494

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
113.	सहयोग एवं उपहार योजना/ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	100	45.78	224.84
114.	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	16069	9913	25962
115.	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	6291	3714	10226
116.	मुख्यमंत्री लघु सीमान्त वृद्धावस्था कृषक पेंशन योजना	करोड़ रुपए	574	391	1144
117.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	1737	965	2866
118.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	563	526	1203
119.	राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	394	298	748
120.	पालनहार योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	1960	867	2988
121.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	4910	2840	7006
122.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	5.11	3.10	8.59
123.	अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	124450	118319	305409
124.	अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	226.63	154.98	410.01
125.	अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी	संख्या	186819	147475	370215
126.	अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत व्यय	करोड़ रुपए	16.08	12.17	30.06
127.	अनुसूचित जनजाति अनुप्रति योजना/ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी	संख्या	8028	518	8121
128.	अन्य पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी	संख्या	7996	175	8098
129.	अति पिछड़ा वर्ग अनुप्रति योजना/ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी	संख्या	1749	107	1798
130.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोडे गए नए पेंशनर्स	संख्या	1060625	318694	3575757

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि	वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की 2 वर्ष की उपलब्धि	वर्ष 2024 से पूर्व के 5 वर्ष की उपलब्धि
131.	जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु केन्द्र व राज्य द्वारा आवंटित राशि	करोड़ रुपए	2228.65	1206.78	4076.89
132.	जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु केन्द्र व राज्य द्वारा आवंटित राशि के विरूद्ध कुल व्यय	करोड़ रुपए	1621.93	1196.72	3554.09
133.	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवंटित राशि	करोड़ रुपए	1913.39	674.83	2723.96
134.	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय	करोड़ रुपए	1478.56	644.96	2463.20
135.	विदेशी पर्यटकों का आगमन	करोड़	0.40	0.21	0.42
136.	पर्यटक स्थलो के विकास/ संरक्षण पर व्यय	करोड़	156.66	32.65	290.92
137.	विभिन्न सिंचाई परियोजना एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर व्यय	करोड़ रुपए	10876	4112	14380
138.	लघु सिंचाई परियोजना पूर्ण	संख्या	5	0	6
139.	पूर्ण की गई लघु सिंचाई परियोजना से उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सिंचाई सुविधा	हेक्टेयर	6990	0	7610
140.	प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभान्वित महिलाएं	संख्या	1026042	749448	1484009
141.	प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी गई सहायता राशि	करोड़ रुपए	536.80	331.90	665.52
142.	नि:शुल्क बैसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना से लाभान्वित महिलाएं	संख्या	147536	92741	381995
143.	सामूहिक विवाह योजना के तहत दी गई अनुदान राशि	करोड़ रुपए	21.08	16.65	35.61

संकल्प से सिद्धि

बजट घोषणाओं एवं संकल्प पत्र के बिन्दुओं की क्रियान्विति

(दिनांक 02.02.2026 तक की स्थिति)

क्र.सं.	विवरण	कुल बिन्दु/घोषणाएं	क्रियान्विति पूर्ण, प्रगतिरत एवं स्वीकृति जारी
1.	**संकल्प पत्र 2023**	**392**	**282 (72%)**
2.	**कुल बजट घोषणाएं**	**2718**	**2434 (90%)**
	i. बजट घोषणाएं 2024-25	1277	1188 (93%)
	ii. बजट घोषणाएं 2025-26	1441	1246 (86%)

*पृष्ठ 59 से 74 तक समस्त आंकड़े आयोजना विभाग, राजस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक से लिए गए हैं।

अद्भुत वास्तुकला का

अनुपम उदाहरण

नीलकंठ महादेव, अलवर

सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में, एक खड़ी और चुनौतीपूर्ण पगडंडी पर स्थित यह मंदिर राजोरगढ़ किले के ध्वस्त अवशेषों से घिरा हुआ है। मंदिर में प्राप्त अभिलेख 961 ईस्वी के हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजाधिराज मथनदेव बड़गुर्जर ने कराया था, जो प्रतिहार वंश के एक शासक थे। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट राजस्थानी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, यहां बारीक नक्काशी, भव्य स्तंभ और आकाश की ओर उठते सुसज्जित शिखर इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं।

छाया एवं आलेख-**अमन हरसाना**

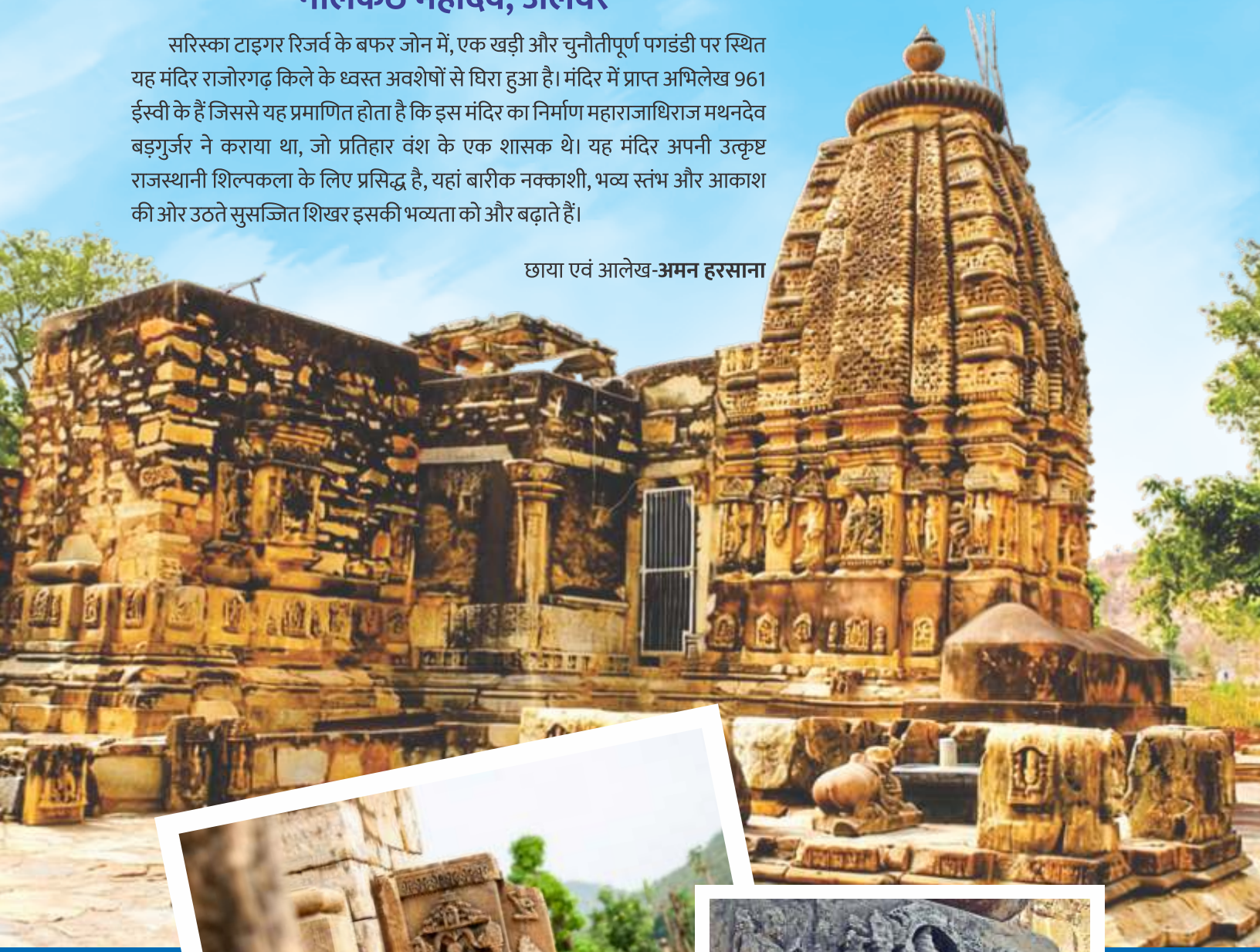

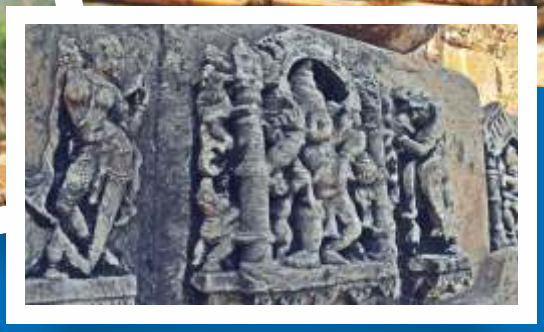

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

वंदे मातरम्@150

वन्दे मातरम्

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैधृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम्।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

- बंकिम चन्द्र चटर्जी

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, राकेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - डॉ. रजनीश शर्मा, मैसर्स प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर से मुद्रित, (18,000 प्रतियां) 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 76, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 1,00,000